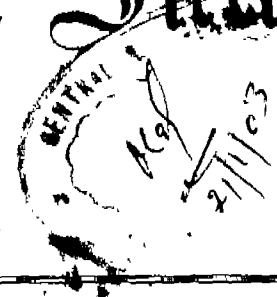


भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 154]
No. 154]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 24, 2002/आषाढ़ 3, 1924
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 24, 2002/ASADHA 3, 1924

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

प्रारंभिक जांच परिणाम

नई दिल्ली, 24 जून, 2002

विषय : यूरोपीय संघ, सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका से फिनोल के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच-प्रारंभिक जांच परिणाम।

सं. 14/4/2002-डीजीएडी.— वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आंकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 को ध्यान में रखते हुए:-

(क) प्रक्रिया

2. निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया गया है:-

- (i) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) को उपरोक्त नियमों के अंतर्गत घरेलू उद्योग की ओर से मै0 हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि0 (एमओसीएल) से लिखित याचिका प्राप्त हुई है, जिसमें यूरोपीय संघ, सिंगापुर तथा दक्षिण अफ्रीका (जिन्हें इसमें इसके बाद सम्बद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फिनॉल (जिसे इसमें इसके बाद सम्बद्ध वस्तु कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाया गया था।

- (ii) प्राधिकारी ने उक्त नियम-5 के उप-नियम-5 के अनुसार जांच की कार्रवाई शुरू करने से पहले याचिकाकर्ता द्वारा किए गए पाटन संबंधी आवेदन की प्राप्ति के विषय में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों/प्रतिनिधियों को सूचित किया ।
- (iii) प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 तथा 27 के तहत सीमाशुल्क उपशीर्ष सं० 2907.11 तथा 2707.60 के अंतर्गत आने वाले फिनाँल के आयातों से संबंधित पाटनरोधी कार्यवाही शुरू करने के बारे में एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसे 15 फरवरी, 2002 को भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित किया ।
- (iv) प्राधिकारी ने उक्त सार्वजनिक सूचना की एक प्रति ज्ञात निर्यातकों, आयातकों, उपयोगकर्ता, उद्योग एसोसिएशनों तथा शिकायतकर्ताओं को भेजी और उन्हें अपने विचार-लिखितरूप में प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया ।
- (v) प्राधिकारी ने उपरोक्त नियम-6 के उप-नियम(3) के अनुसार याचिका की प्रति सभी ज्ञात निर्यातकों और भारत स्थित संबद्ध देश के दूतावासों/प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई ।
- (vi) प्राधिकारी ने संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए संबद्ध देशों के निम्नलिखित निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी:-
- (क) फिनोलकैमी जीएमबीएच, पोस्टफैक 508, जर्मनी ।
 - (ख) एनीकेम, पिआजा बोल्डीटोनी 1, इटली ।
 - (ग) मितसुई कम्पनी लिमिटेड, 16 रैफल्सक्वे, सिंगापुर ।
 - (घ) मेरीसोल, सेसोलबर्ग, दक्षिण अफ्रीका ।
- (vii) संबद्ध देशों के नई दिल्ली स्थित दूतावासों/प्रतिनिधियों को जांच की शुरुआत के संबंध में भी सूचना दी गई थी तथा यह अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय में प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए सलाह दें ।
- (viii) संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित प्रयोगकर्ताओं/आयातकों को प्रश्नावली भेजी गई थी:-

(क) मुख्य उपयोक्ताओं की खंडीय रूप में सूची**पीएफ रेसिन्स**

(क) पीएफ मोलडिंग पाऊडर: एक्सप्रो इंडिया, सिमको बिरला लिमिटेड खंड, काँदीवली पश्चिम, मुम्बई-400067

(ख) लेमीनेट्स, बेकलाइट हाइलम लिमिटेड, सनथनगर, हैदराबाद, एपी

(ग) प्लाईबुड/पार्टिकल बोर्ड: ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रत्नागिरी, महाराष्ट्र

(घ) फाउंडरीज/एब्रेसिव्स: गार्गी हतीन्स, एलबर्टस प्रा० लि०, एक वसन्त विहार काम्पलेक्स, चैम्बूर, मुम्बई-400074

दयाइयाँ तथा भेषज

आल्टा लैबोरेट्रीज लिमिटेड, आल्टा भवन, सेनापति बापत मार्ग, दादर, मुम्बई-400028 ।

पेस्टनाभी तथा कीटनाशी:- यूनाइटेड फासफोरस लिमिटेड, रेडीमनी टेरेस, डाक्टर एनी बेसेंट रोड, मुम्बई ।

सिन्टैन्स

कलर कैम लिमिटेड, मुम्बई आगरा रोड, बलकम, थाने, मुम्बई ।

एल्काइल फिनोलस और डाइफिनाइल ऑक्साइड

हरदिलिया केमिकल्स लिमिटेड, 13वां तल, एयर इंडिया बिल्डिंग, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई ।

(ख) भारतीय आयातकों (व्यापारियों) के पते

सी०जे० शाह एंड कम्पनी

105, बजाज भवन

10वां तल, नरीमन प्वाइंट

मुम्बई-400021

हरेश कुमार एंड कम्पनी

1212, मेकर चैम्बर्स-5

जमनालाल बजाज रोड,

नरीमन प्वाइंट

मुम्बई-400021

पीसीएल इंडस्ट्रीज

एम-105, कनाट प्लेस

नई दिल्ली-110001

कांतिलाल मनीलाल एंड कम्पनी

16, प्रिसेंस स्ट्रीट

मुम्बई-400003

सोनकामल एंटरप्राइजेज

10, देव दर्शन एपार्टमेंट

ओल्ड नगरदास रोड

अन्धेरी (पूर्व)

मुम्बई-400069

खेतान ब्रदर्स

सी-17, दलिया इंडस्ट्रीयल एरिया

ऑफ न्यू लिंग रोड

लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एस्टेट के सामने

अन्धेरी (पश्चिम)

मुम्बई-400058

शुभम डाइज एंड केमिकल्स लिमिटेड

1/26 रूप नगर

दिल्ली-110007

(ग) उपभोक्ता उद्योगों के घरेलू संघ

क. इंडियन एसोसिएशन ऑफ यूजर इंडस्ट्रीज

16, मुम्बई समाचार मार्ग, मुम्बई-400023

ख. सोसाइटी ऑफ थर्मोसेटिंग इंडस्ट्रीज

टिपको, रानी सती मार्ग, मालद (पूर्व)

मुम्बई-400097

ग. इंडियन लेमिनेट्स मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशनस

दास चैम्बरस, मुम्बई-400023

(ix) मितसुई फिनाँल सिंगापुर पी, सिंगापुर ने पत्र प्राप्ति के विलम्ब को ध्यान में रखते हुए उत्तर देने के लिए कुछ और समय की मांग की थी । मैसर्स केसर पैट्रो प्रोडक्ट्स, जो संबद्ध वस्तुओं का उपयोगकर्ता, हैं ने भी उत्तर देने के लिए समय बढ़ाने की मांग की थी क्योंकि घरेलू उद्योग द्वारा दायर की गई याचिका में उसका नाम नहीं था । निर्यातक तथा उपयोक्ता, दोनों को एक अतिरिक्त सप्ताह की अनुमति दी गई थी ।

- (x) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के अगोपनीय अंश को एक सार्वजनिक फाईल के रूप में उपलब्ध रखा और इसे हितबद्ध पार्टियों द्वारा निरीक्षण हेतु खुला रखा ।
- (xi) इस अधिसूचना में *** से हितबद्ध पार्टियों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गयी सूचना प्रदर्शित होती है और नियमों के तहत प्राधिकारी द्वारा उसे गोपनीय ही माना गया है ।
- (xii) इस जांच में 1 अप्रैल, 2001 से 31 दिसम्बर, 2001 तक की अवधि शामिल है ।
- (xiii) याचिकाकर्ता से क्षति के संबंध में अतिरिक्त ब्यौरा मांगा गया था जिसे भी प्रस्तुत कर दिया गया था ।
- (xiv) प्राधिकारी ने आवश्यक समझी गयी सीमा तक घरेलू उद्योग की मौके पर जांच की ।
- (xv) याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गयी सूचना के आधार पर सामान्यता स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर संबद्ध वस्तु की ईष्टतम उत्पादन लागत तथा भारत में इसकी निर्माण एवं बिक्री लागत निकालने के लिए घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत का भी विश्लेषण किया गया ताकि यह सुनिश्चित हो जाए की पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क लगाना घरेलू उद्योग को हो रही क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा ।
- (xvi) जांच शुरूआत संबंधी सूचना की प्रतियां व्यापक परिचालन के लिए फिक्की, सीआईआई, एसोचैम इत्यादि को भी भेजी गयी ।

ख. याचिकाकर्ता के विचार

3. याचिकाकर्ता ने अपने निवेदन में निम्नलिखित प्रमुख बातें कही हैं :-

(i) वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद फिनोल है जिसें कारबोलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है । इसका उत्पादन हवा के उच्च तापमान और दबाव के द्वारा क्यूमीन के आक्सीकरण द्वारा किया जाता है । इसके बाद उत्पाद की क्षारीय धुलाई की जाती है और उच्च शक्ति पर सांद्रित किया जाता है । इसके बाद इसका H_2SO_4 के साथ मिश्रण किया जाता है जिसके कारण भेदन क्रिया होने से फिनोल और एसीटोन प्राप्त होते हैं । इसके बाद अम्लता को समाप्त करने के

लिए इसकी धुलाई की जाती है और आसवन कॉलमों की श्रृंखला में आसवन करके इससे फिनोल और एसीटोन प्राप्त किए जाते हैं ।

(ii) इसे सीमाशुल्क अधिनियम के अध्याय 29 के सीमाशुल्क उप-शीर्ष 2907.11 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है । तथापि अध्याय 27 के उप-शीर्ष 2707.60 के अंतर्गत भी इसका आयात किया जाता है ।

(iii) भारत में फिनोल के तीन उत्पादक हैं जिन्होंने फिनोल उत्पादन की क्षमता का सृजन किया है । याचिकाकर्ता के अतिरिक्त, मैसर्स हरदिलिया कैमिकल्स लिमिटेड और मैसर्स नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन ने भी फिनोल उत्पादन की क्षमता का सृजन किया है । तथापि, याचिकाकर्ता ने यह अनुरोध किया है कि नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन फिनोल का अपेक्षाकृत काफी छोटा उत्पादक है ।

(iv) भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित फिनोल तथा संबद्ध देशों से निर्यातित फिनोल में कोई अंतर नहीं है । भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित फिनोल तथा संबद्ध देशों से आयातित फिनोल भौतिक तथा रासायनिक विशिष्टताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, (संबद्ध देशों के अधिकांश उत्पादकों द्वारा अनुपालित) कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण वितरण तथा विणन और वस्तु के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संबंध में तुलनीय है । ये दोनों तकनीकी तथा वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं । उपभोक्ता दोनों का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर कर रहे हैं । याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित तथा संबद्ध देशों से आयातित फिनोल को पाटनरोधी नियमों के अनुसार समान वस्तु माना जाना चाहिए ।

(v) जहाँ तक संबद्ध देशों के मामले में सामान्य मूल्य का संबंध है याचिकाकर्ता संबद्ध देशों में फिनोल की कीमतों के संबंध में अथवा निर्यातकों की कीमत रुचियों के संबंध में साक्ष्य जुटाने में समर्थ नहीं रहा है । वे संबद्ध देशों से अन्य देशों (सिंगापुर को छोड़कर) को हुए निर्यातों के किसी भी साक्ष्य को जुटाने में भी असमर्थ रहे हैं । केवल सिंगापुर के मामले में वे उस कीमत का साक्ष्य प्राप्त करने में सफल हुए हैं जिस पर सिंगापुर के उत्पादक ने विभिन्न देशों को फिनोल निर्यात किया है । याचिकाकर्ता का विश्वास है कि जिस कीमत पर भारत को सामग्री निर्यात की गई है तथा जिस कीमत पर सिंगापुर के निर्यातक ने अन्य देशों को सामग्री निर्यात की इन कीमतों में बहुत अंतर है । वास्तव में सिंगापुर को निर्यातक उत्पाद का जिस कीमत पर भारत को निर्यात कर रहा है,

वह भारत में फिनोल की कीमत का सीमा निर्धारण कर रहा है और अन्य देशों के उत्पादकों को कीमतों को घटाने तथा पाटन का सहारा लेने के लिए विवश कर रहा है। याचिकाकर्ता सिंगापुर से भारत तथा दास प्रमुख देशों को फिनोल के निर्यात के संबंध में सूचना प्राप्त करने में सफल हुआ है। सामान्य मूल्य का निर्धारण सिंगापुर से मलेशिया तथा थाइलैंड को हुए निर्यात के आधार पर किया गया है। जहाँ तक यूरोपीय संघ तथा दक्षिण अफ्रीका का संबंध है याचिकाकर्ता ने जिस कीमत पर भारत में मूल कच्ची सामग्री का आयात किया गया को लेने के पश्चात् उत्पादन की परिकलित लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है।

(vi) याचिकाकर्ता ने डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता के प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत का दावा किया है। तथापि, जून, 2001 तक की अवधि के लिए भारत में फिनोल के आयातों की मात्रा तथा मूल्य के निर्धारण के लिए उक्त सूचना पर विश्वास किया गया है। जाँच अवधि की बाद की अवधि (जुलाई से आगे), याचिकाकर्ता ने गौण स्रोतों (कांडला पत्तन से) सूचना प्राप्त की है क्योंकि उनका मानना है कि डीजीसीआई एंड एस के आंकड़े पूर्ण नहीं हैं तथा इनमें संपूर्ण आयात प्रदर्शित नहीं होते हैं। सिंगापुर के मामले में याचिकाकर्ता ने सिंगापुर व्यापार सांख्यिकी के अनुसार सिंगापुर से भारत को निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं का साक्ष्य प्रस्तुत किया है।

(vii) याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि सभी संबद्ध देशों से पाटन का मार्जिन न केवल न्यूनतम से कम है अपितु अत्यधिक भी है। वास्वत में आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण उचित है क्योंकि संबद्ध देशों से हुए निर्यात, भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग के द्वारा प्रस्तावित कीमतों से सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसलिए प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह संबद्ध देशों से घरेलू उद्योग को हुई क्षति का संचयी निर्धारण करें।

(viii) आयात के आंकड़ों से यह पता चलता है कि संबद्ध देशों से हुए आयातों की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हुई है। रक्षोपाय शुल्क लगाने के बावजूद आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है।

(ix) विभिन्न आर्थिक मापदंडों से यह संकेत मिलता है कि याचिकाकर्ता को संबद्ध देश से हुए आयात के कारण क्षति हुई है। चालू वर्ष में उत्पादन और क्षमता उपयोग में भारी कमी आई है। घरेलू उद्योग संबद्ध देशों से हुए पाटन के कारण उत्पादन को कम करने के लिए विवश हुआ है।

(x) आयातित फिनोल की कीमतों में तेजी से गिरावट आई जिसके फलस्वरूप कीमत में भारी मन्दी आई है। आयातित फिनोल की कीमतों को जब कीमत वृद्धि में समायोजित किया गया तो वे वर्ष 1998-99 के पहले से ही चल रहे न्यून स्तर से कम हो गई जिसमें सुरक्षापाय जांच की पहली अवधि शामिल थी।

(xi) याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि जिस कीमत (मूल सीमाशुल्क को शामिल करने के पश्चात) पर सामग्री का आयात किया जाता है वह न केवल घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है, अपितु इससे याचिकाकर्ता की पूरी उत्पादन लागत भी प्राप्त नहीं हो रही है। इसलिए आयातों के कारण बाजार में कीमत में भारी कटौती, ह्रास और कमी आ रही है।

(xii) 9 इस प्रकार घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत उत्पादन लागत से बहुत कम थी जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को गंभीर वित्तीय घाटा हुआ।

(xiii) इस तरह घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न आर्थिक मापदंडों से सामूहिक और संचयी रूप से यह प्रमाणित होता है कि घरेलू उद्योग को रक्षोपाय शुल्क लागू होने के बावजूद क्षति हुई है और यह क्षति प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध देशों से हुए पाटित आयातों के कारण हुई है।

(ग) निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षदारों के विचार:-

4 निम्नलिखित निर्यातकों और निर्यातक संगठनों से उत्तर प्राप्त हुए हैं:-

- (i) मित्सुई एंड कम्पनी लि०, सिंगापुर ब्रांच, सिंगापुर
- (ii) मित्सुई फिनेल सिंगापुर, पीटीई लि०, सिंगापुर
- (iii) मेरीसोल आरएसए (पीटीवी) लि०, जॉहासबर्ग, दक्षिण अफ्रीका

5. उपरोक्त द्वारा किये गये अनुरोध और/अथवा उपलब्ध कराई गई सूचना निम्नानुसार हैं:-

- (i) मित्सुई एण्ड कं० लि०, सिंगापुर ब्रांच, सिंगापुर
- (क) मै० मित्सुई एण्ड कं० लि० ने यह माना है कि वे भारत में किसी निर्यात का पाटन नहीं करते हैं और भारत के स्थनीय उत्पादकों को कोई क्षति नहीं पहुँचाते हैं।

(ख) भारत को हुए निर्यातों की कीमत का निर्धारण विश्व की आपूर्ति/मांग के संतुलन तथा अंतर्राष्ट्रीय कीमतों एवं अन्य आपूर्तिकर्ताओं के साथ प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए किया गया है ।

(ग) वर्ष 2001 में अत्यधिक खराब आर्थिक स्थिति के कारण समूचे विश्व में फिनेल की मांग में तेजी से गिरावट आई । वर्ष 2001 में फिनाॅल की कुल मांग लगभग 6.5 मी० टन की थी जो पूर्ववर्ती वर्ष की मांग की तुलना में 3% कम थी । तथापि, फिनोय की कीकुल उत्पादन क्षमता लगभग 8 मी० टन पर पहुँच गई जिसका तात्पर्य यह है कि 2001 के समूचे वर्ष के दौरान औसत संयंत्र उपयोग का अनुपात लगभग 82-83% माना गया था जो पिछले 5 वर्ष के मद्दे नजर अत्यधिक कम था । उदाहरणार्थ, वर्ष 2001 की शुरुआत में एशिया में मानक बाजार कीमत लगभग 600 मी०टन अमरीकी डालर सीआईएफ थी जो 2001 के अंत में घटकर 400/मी०टन अमरिकी डालर सीआईएफ हो गई ।

(घ) भारतीय अर्थव्यवस्था में फिनेल की भारतीय मांग में लगातार वृद्धि होती रही है और तदनुसार आयातित फिनेल की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । जहाँ कुल मांग लगभग 110-120 किलो टन प्रति वर्ष होने का अनुमान है वहीं सभी घरेलू उत्पादकों का उत्पादन केवल लगभग 60 किलो टन प्रति वर्ष का है जिसका तात्पर्य है कि भारत को 50-60 किलो० टन प्रति वर्ष के लगातार आयात की जरूरत है ।

(ङ.) मितसुई फिनोल सिंगापुर लि० (एमपीएचएस) विश्व के नवीनतम और वृहदतम संयंत्रों में से एक है और यह सतत उत्पादन, उच्च उत्पादकता और कम उत्पादन लागत के संबंध में सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी है । सिंगापुर से हुए आयातों के परिणामस्वरूप अनेक ग्राहक अपनी लाभप्रदता में वृद्धि कर सकते थे जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी योगदान मिलना चाहिए था । यद्यपि, घरेलू उत्पादकों के सामने अक्सर उत्पादन संबंधी समस्याएँ और अस्थिर आपूर्ति की समस्या बनी रहती है । वस्तुतः घरेलू उद्योग को जो भारी क्षति हो रही है वह सिंगापुर के उत्पाद के आयात के कारण

नहीं हुई है बल्कि घरेलू उत्पादकों के अप्रतिस्पर्धी स्वरूप और अपने उत्पादन और आपूर्ति की प्रणाली के पुनर्गठन में हुए विलम्ब के कारण हुई है ।

(च) निर्यातक ने आगे बताया है कि फिनेल की कीमत में अचानक अधिक माँग होने और आपूर्ति में असंतुलन आने तथा कच्ची सामग्री की कीमत में भारी गिरावट आने के कारण तेजी से कमी आई है । कीमत में उक्त गिरावट न केवल भारत में आई है बल्कि समूचे विश्व में आई है ।

(छ) फिनोल स्वयं रासायनिक विशेषताओं के संबंध में भिन्न नहीं है । तथापि, समग्र सेवा एवं गुणवत्ता नियंत्रण तथा अंतिम ग्राहकों के लिए फैक्ट्री में किये गये मूल्यवर्धन भिन्न-भिन्न है ।

(ज) एचओसीएल संयंत्र काफी पुराना है और उसका उत्पादन अनुपात इतना खराब है जिससे कि लागत भी प्राप्त नहीं होती है । दूसरी ओर, एमबीएचएस के पास अद्यतन उन्नत प्रौद्योगिकी है ।

(झ) सिंगापुर में फिनेल के काफी अधिक उपभोक्ता है और इस उपभोक्ता की कीमत को सामान्य मूल्य के रूप में लिया जाना चाहिए ।

(ण) जहाँ तक संबद्ध देशों से आयातों में समग्र रूप से हुई पर्याप्त वृद्धि का संबंध है निर्यातक ने यह माना है कि भारत में माँग में काफी वृद्धि हुई है जबकि सिंगापुर में नई क्षमता का निर्माण किया गया है । इसके अलावा, भारत के बाहर विश्व माँग में वर्ष 2001 के बाद पर्याप्त कमी आई है । आयातों में वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के कारण हुई है और न कि पाटित कीमतों के कारण । यह तथ्य कि एचओसी की बिक्रियों में 30 किलो टन से कम की गिरावट आई है, यह उनकी तकनीकी और वित्तीय समस्या के कारण आई है ।

मितसुई फिनोल सिंगापुर पीटीई लि० (एमपीसीएल) सिंगापुर ब्रांच

(क) मितसुई फिनेल सिंगापुर पीटीई लि० का स्वामित्व मै० मितसुई केमिकल्स इंक जापान और मितसुई एंड कं० जापान के पास है ।

(ख) याचिकाकर्ता ने वही तर्क प्रस्तुत किया है जोकि निर्यातक मै0 मितसुई लि0 कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किया गया है जैसाकि पूर्ववर्ती पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है । इन्हें संक्षिप्ता की वजह से दोहराया नहीं जा रहा है । तथापि उनके सामान्य मूल्य एवं निर्यात कीमत पर उनके अनुरोध के अनुसार संगत शीर्षों में अलग से विचार किया जा रहा है ।

मै0 मेरीसोल आरएसए (पीटीवी), दक्षिण अफ्रीका

(क) मै0 मेरीसोल आरएसए (पीटीवाई) ने प्रश्नावली का उत्तर दिया है और अपने अनुरोधों में तर्क दिए हैं ।

(ख) आधार- याचिकाकर्ताओं ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि जांच अवधि के दौरान उनका उत्पादन घरेलू उत्पादन के 50% से कम बनता था । नियम 5(3) के अनुसार वैध आवेदन के लिए निम्नलिखित दो शर्तों को पूरा करना होता है;

- (i) आवेदन का स्पष्ट रूप से समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादकों का उत्पादन भारत में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए समान वस्तुओं के कुल उत्पादक के 25% से कम नहीं होना चाहिए; और
- (ii) आवेदन का स्पष्ट रूप से समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादकों का उत्पादन आवेदन का स्पष्ट रूप से समर्थन करने वाले और विरोध करनेवाले उत्पादकों द्वारा किए गए समान वस्तुओं के कुल उत्पादन के 50% से अधिक होना चाहिए । जब याचिकाकर्ता उक्त परीक्षण के भाग (क) की शर्त को पूरा कर सकते हैं तो उक्त परीक्षण के भाग (ख) का सत्यापन करने का भार निर्दिष्ट प्राधिकारी पर होता है और ऐसे समय तक यह अनुरोध है कि इस जांच की शुरुआत को अधिकारातीत माना जाए ।
- (iii) हरदिलिया का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है: यह उल्लेखनीय है कि मै0 हरदिलिया का स्वामित्व 1 जुलाई, 2001 को सेनेक्डी ग्रुप के पास चला गया था मै0 मेरीसोल आरएसए (पीटीवाई) का मानना है कि मै0 हरदिलिया को जांच अवधि के दौरान कोई क्षति नहीं पहुँची है और भारत में घरेलू उद्योग को हुई किसी क्षति का निर्धारण करते समय इस तथ्य की जांच की

जानी चाहिए अन्यथा मै0 हरदिलिया केमिकल्स लि0 को किसी क्षति का खुलासा किये बिना पाटनरोधी शुल्क का लाभ मिल जाएगा ।

(iv) क्षति मार्जिन का निर्धारण:- याचिकाकर्ता ने उत्पाद पर मौजूदा रक्षोत्पाद शुल्क पर विचार किये बिना पहुँच मूल्य का दावा किया है । घरेलू उद्योग के लिए क्षति मार्जिन यदि कोई हो का निर्धारण करने के लिए पहुँच मूल्य की गणना करने में रक्षोपाय पर विचार करना चाहिए क्योंकि ऐसा न करने पर घरेलू उद्योग को दोहरे संरक्षण, पहला उनकी अपनी अकुशलता और दूसरा आरोपित पाटन द्वारा हुई क्षति का लाभ मिलेगा । याचिकाकर्ताओं के लिए क्षति मार्जिन में इन दोनों को उद्घाटित किया जाना चाहिए ।

(v) रक्षोपाय शुल्क और क्षति:- चूँकि भारत में इस प्रकार का यह पहला मामला है जिसमें रक्षोपाय शुल्क के लंबित रहने के दौरान पाटनरोधी शुल्क के लिए याचिका दायर की गई है । इसलिए, माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी को घरेलू उद्योग की अकुशलता के कारण उसे हुई क्षति पर विचार नहीं करना चाहिए ।

आयातक एवं उपभोक्ता

6. निम्नलिखित आयातकों एवं उपभोक्ताओं ने प्रश्नावली का उत्तर दिया है:-

(क) ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज: उन उद्योगों के नाम, जिन्होंने इस अभ्यावेदन द्वारा अपने अनुरोध किए हैं-

(i) रेजिन्स एण्ड प्लास्टिक्स लि0

(ii) नीलक्स इंडिया लि0

(iii) यूनाइटेड फास्फोरस लि0

(iv) अलका लेबोरेट्री लि0

(v) डूजूडवाला रेअन्स एण्ड टैरपेन्स लि0

(vi) आइवीपी लि0

(vii) डूजूडवाला पेपर केमिकल्स लि0

(viii) गार्गी हटेन्स अल्बर्टस लि0

- (ix) डूणेडवाला प्रोडक्ट्स लि०
- (x) मार्बल थर्मोसेट्स प्राइवेट लि०
- (xi) एक्सप्रो इंडिया लि०
- (xii) बीएसएसएफ इंडिया लि०
- (xiii) यूनाइटेड मेटाकेम प्रा० लि०
- (xiv) कलर केम लि०

- (ख) मै० केसर पेट्रोप्रोडक्ट्स लि०
- (ग) एसोसिएशनस ऑफ यूजर्स एण्ड कंजूमर्स ऑफ फिनोल

7. उपर यथा उल्लिखित विभिन्न उद्योग एसोसिएशनों तथा उपयोक्त संगठनों द्वारा प्रस्तुत किए गए महत्वपूर्ण मुद्दे/तर्क निम्नानुसार हैं-

(क) पाटनरोधी आवेदनों को सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन तथा संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियम, 1995 के उपबंधों के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से दायर किया जाता है। संगत धारा पाटनरोधी अधिनियम का नियम 5 है जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया जाता है।

5. जांच शुरू करना

- (1) उप-नियम (4) में किए गए उपबंध को छोड़कर निर्दिष्ट प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से लिखित आवेदन प्राप्त होने पर किसी आरोपित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने के लिए जांच शुरू करेगा।
- (2) उप-नियम (1) के अंतर्गत कोई आवेदन उस स्वरूप में होगा जैसाकि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया जाए और आवेदन का समर्थन निम्नलिखित के संबंध में साक्ष्य द्वारा किया जाएगा:-

- (क) पाटन
- (ख) क्षति, जहां लागू हो; और
- (ग) जहां लागू हो, ऐसे पाटित आयातों और आरोपित क्षति के बीच कारणात्मक संबंध ।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी उप-नियम (1) के तहत किए गए किसी आवेदन के अनुसरण में तब तक कोई जांच शुरू नहीं करेगा जब तक कि:

(क) वह समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों द्वारा व्यक्त किए गए उक्त आवेदन के समर्थन अथवा विरोध की मन्त्रा की जांच के आधार पर यह निर्धारित न कर ले कि उक्त आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से दायर किया गया है;

परन्तु यदि आवेदन का स्पष्ट रूप से समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादकों का उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा किए जा रहे समान वस्तु के कुल उत्पादन के 25% से कम बनता है तो कोई जांच शुरू नहीं की जाएगी, और

(ख) वह आवेदन में दिए गए साक्ष्यों की यथार्थता और पर्याप्तता की जांच न कर ले और व्यय को इस बात के प्रति संतुष्ट न कर ले कि निम्नलिखित के बारे में पर्याप्त साक्ष्य हैं-

- (i) पाटन
- (ii) क्षति जहां लागू हो; और
- (iii) जहां लागू हो, जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए ऐसे पाटित आयातों और आरोपित क्षति के बीच कारणात्मक संबंध ।

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजनार्थ आवेदन को उस स्थिति में घरेलू उद्योग अथवा उसकी ओर से किया गया माना जाएगा यदि इसका समर्थन उन घरेलू उत्पादकों द्वारा किया गया

हो जिनका सामूहिक उत्पादन इस आवेदन का समर्थन अथवा विरोध करने वाले घरेलू उद्योग के उस भाग द्वारा उत्पादित समान वस्तु के कुल उत्पादन के 50% से अधिक बनता हो ।

पाटनरोधी नियमों के उपबंधों के तहत याचिका का समर्थन उन एककों द्वारा अपेक्षित होता है जिनका उत्पादन समूचे घरेलू उद्योग के उत्पादन का कम से कम 25% बनता हो/नियमों के स्पष्टीकरण में आगे यह निर्धारित किया गया है कि आवेदन का समर्थन उन उत्पादकों के कम से कम 50% द्वारा किया जाना चाहिए जो आवेदन का समर्थन अथवा विरोध करते हैं । दूसरे शब्दों में पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के उपबंध के तहत किसी वैध आवेदन के रूप में विचार करने के लिए किसी आवेदन की दो प्रकार की जांच करनी होती है अर्थात् कुल उत्पादन का 25% और उन उत्पादकों का 50% जो आवेदन का समर्थन व विरोध करते हैं । निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए यह अनिवार्य है कि वह यह सुनिश्चित करें कि दोनों ही परीक्षण मामला शुरू करने से पूर्व कर लिए जाते हैं ।

इस मामले में याचिकाकर्ता अर्थात् एचओसीएल का स्पष्टरूप से उत्पादन घरेलू उद्योग के कुल उत्पादन का 46% बनता है । निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह पता करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है कि क्या आवेदन का कोई विरोध किया गया है अथवा नहीं इस संबंध में नियम 5(3) (ख) को देखना महत्वपूर्ण है जिसमें निर्दिष्ट प्राधिकारी पर केवल जांच शुरू करने से पूर्व आधार का निर्धारण करने का दायित्व डाला गया है ।

वस्तुतः कार्रवाई के इस पहलू का "निर्धारण" जांच से पूर्व करना अपेक्षित होता है । चूंकि निर्दिष्ट प्राधिकारी उक्त अनिवार्य परीक्षणों को करने में विफल रहे हैं और एक पूर्वशर्त को पूरा करने में विफल रहने के कारण जांच की शुरूआत जारी नहीं रह सकती ।

ख. यह नोट करना संगत है कि दिनांक 14.5.99 के रक्षोपाय महानिदेशालय के अंतिम जांच परिणामों में एचओसीएल और हरदीलिया कैमिकल्स लि० के मूल आवेदन पर रक्षोपाय महानिदेशालय

द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि भारत में फेनोल के पाटन का कोई प्रमाण नहीं है और इसलिए इस मामले को रक्षोपाय शुल्क हेतु रक्षोपाय महानिदेशालय द्वारा जांच करने के लिए उचित समक्षा गया था ।

ग. यह देखा जाता है कि वर्तमान याचिका में एचओसीएल ने पूर्णतः विरोधी दृष्टिकोण अपनाया है और यह दावा किया है कि भारत में फिनोल का पाटन सिंगापुर व्यापार सांख्यिकी में प्रकाशित कुछेक आंकड़ों के आधार पर किया जा रहा है । एचओसीएल अभी भी निर्यातक देशों के घरेलू बाजारों में फिनोल की बिक्री कीमत के बारे में कोई आंकड़ा प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं रहे हैं । इसके अलावा इस आधार पर कि यह पाटन का मामला नहीं है रक्षोपाय शुल्क का लाभ लेने के बाद एचओसीएल द्वारा अब फिनोल पर पाटनरोधी शुल्क हेतु आवेदन करके दोहरा लाभ प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है ।

घ. एचओसीएल ने दावा किया है कि फिनोल का पाटन अप्रैल, 01 से शुरू हुआ है । उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि जहाँ तक सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका का संबंध है अप्रैल-दिसम्बर, 01 की अवधि में कोई रक्षोपाय शुल्क लागू नहीं था । इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि फेनोल निर्माताओं द्वारा इस विषय पर महानिदेशालय (रक्षोपाय) को इस आधार पर अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए हैं कि अप्रैल, 01 से दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर से आयातों में वृद्धि हुई है और जुलाई, 01 में आयातों में काफी अधिक वृद्धि हुई है । इस अभ्यावेदन के आधार पर महानिदेशालय (रक्षोपाय) ने दिनांक 11 दिसम्बर, 01 के अपने अंतिम जाँच परिणामों में मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर से हुए आयातों पर रक्षोपाय शुल्क वसूल करने की सिफारिश की है । इस प्रकार फिनोल निर्माताओं द्वारा सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका से आयातों में वृद्धि हेतु मांगी गई राहत की सिफारिश महानिदेशालय (रक्षोपाय) द्वारा पहले ही की जा चुकी है और पाटनरोधी शुल्क वसूल करके इसी आधार पर आगे और राहत देने का कोई मामला नहीं बनता है ।

ड. पाटनरोधी जाँच की शुरुआत अनुचित है । महानिदेशालय (रक्षोपाय) ने अप्रैल, 2001 से आगे जाँच अवधि को ध्यान में रखते हुए मलेशिया, सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ

रक्षोपाय शुल्क लगाने के बारे में जाँच शुरू की थी । समग्र जाँच के आधार पर महानिदेशालय (रक्षोपाय) ने इन स्रोतों से हुए आयातों पर भी रक्षोपाय शुल्क की सिफारिश की थी ।

च. रक्षोपाय उपबंधों के तहत घरेलू उद्योग को ' गंभीर क्षति ' की अवधारणा के मकाबले पाटनरोधी नियमावली में केवल ' वास्तविक क्षति ' का उपबंध किया गया है । इस प्रकार यदि ' गंभीर क्षति ' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त शुल्क की सिफारिश की गई है तो यह अविचारणीय है कि ' वास्तविक क्षति ' को समाप्त करने के लिए किसी अतिरिक्त धनराशि की जरूरत है जो इसी अधिनियम के तहत कम गंभीर स्थिति है । अतः यह स्पष्ट है कि उस मामले में कोई पाटनरोधी जाँच नहीं की जा सकती जिसमें जाँच की लगभग समान अवधि को ध्यान में रखते हुए रक्षोपाय शुल्क की सिफारिश की गई है ।

छ. याचिकाकर्ता द्वारा यह बताया गया है कि फिनोल का पाटन जुलाई, 2001 से शुरू हुआ है । आगे यह देखा जाता है कि एचओसीएल ने केवल नवम्बर, 2001 तक के आयात संबंधी आंकड़े प्रस्तुत किए हैं और दिसम्बर, 2001 के माह हेतु कोई आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए हैं । अनुरोध है कि पाटनरोधी शुल्क की वसूली जैसे प्रमुख मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए पाँच माह की अवधि बहुत ही कम अवधि है जिसका देश में फिनोल के उपयोक्ताओं पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है ।

ज. उपयोक्ताओं का यह दृष्टिकोण है कि कम स्टॉक से फिनोल की उपलब्धता के बारे में अनिश्चितता उत्पन्न हुई, जिससे फेनोल के उपयोक्ता कुछ महीनों के लिए अपनी जरूरत हेतु योजना बनाने के लिए उद्यत हुए । एसीटोन जोकि फिनोल का सह उत्पाद है, के स्टॉक में भी कमी आई थी और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में एसीटोन के आपूर्तिकर्ता इसे फिनोल की आपूर्ति के साथ जोड़ते हैं । इस प्रकार जुलाई-नवम्बर, 2001 में आयातों का मुख्य कारण फिनोल और एसीटोन की कमी रहा था ।

ज. यह नोट किया जाना है कि जुलाई, 2001 में सिंगापुर में मितसुई कारपोरेशन द्वारा स्थापित 2,00,000 मी०टन की एक बहुत बड़ी अतिरिक्त क्षमता चालू हो गई थी। यह अतिरिक्त क्षमता उन प्रमुख आधारों में से एक आधार पर थी जिसके लिए एसजीडी दो वर्षों के लिए बढ़ाई गई थी।

झ. उत्पादन में कमी के अलावा इस अवधि के दौरान आयातों के लिए एचओसी की मूल्य निर्धारण नीति पर भी आरोपण किया जाना है क्योंकि पर्याप्त स्टॉक की कमी के साथ-साथ मूल्य में संगत वृद्धि के परिणाम स्वरूप आयातों के लिए उपभोक्ता की योजना बनी जिसकी बल्ल में व्यवस्था की जानी अपेक्षित थी।

ञ. अप्रैल-दिसम्बर, 2001 की अवधि के दौरान विभिन्न कारणों से एचओसी संयंत्र को 68 दिनों के लिए बन्द कर दिया गया था, जो फेनोल के कम उत्पादन का एक आधार हो सकता है।

ट. प्रायोक्ताओं का भी कहना है कि आयातों की लागत बढ़ गई है क्योंकि उत्पाद का इंसुलेशन और स्टीम कोइल के साथ विशिष्ट रोड टैकरों में भण्डारण करना होता है जिससे आयातों की पहुँच लागत में लगभग 15% अतिरिक्त लागत की वृद्धि हुई। इस प्रकार घरेलू विनिर्माण आयातों की तुलना में लगभग 15% की कीमत संबंधी लाभ का अर्जन कर रहे हैं।

ठ. फेनोल बाजार पर एचओसी का एकाधिकारिक नियंत्रण : दिनांक 30.06.01 के बाद 2 वर्ष की एसजी की अवधि के विस्तार करने के बाद यूएसए की रोनेक्टेडी, जो फेनोल के भारत और विश्व में मुख्य उपभोक्ता है, के द्वारा एचसीएल के अधिग्रहण के रूप में एक प्रमुख घटना थी। इसके फलस्वरूप सेनेक्टेडी के लिए एचसीएल की फिनोल क्षमता आबद्ध हो गई है और केवल एचओसी भारत में फेनोल के व्यापारिक विनिर्माता के रूप में शेष रहा। एचओसी के एकाधिकार की स्थिति एक ऐसा कारक है जिसे फेनोल पर आगे कोई शुल्क संरक्षण प्रदान करने पर विचार करते समय ध्यान में रखा जाना है।

(ड.) एचओसी, बीपीए जिसका पोलिकारबोनेट के विनिर्माण में उपयोग किया जाता है, के विनिर्माण के लिए अपेक्षित ग्रेड के फेनोल विनिर्माण की स्थिति में नहीं है, एचओसी ने इस ग्रेड के फेनोल का उत्पादन करने में असमर्थता जताई है और इस प्रकार इस ग्रेड को मूल सीमाशुल्कों को छोड़कर अन्य शुल्क संरक्षण से छूट दे देनी चाहिए। बीपीए विनिर्माताओं को पीसी ग्रेड फेनोल के बजाए एचओसी फेनोल के उपयोग के लिए 3,000 प्रति मी० टन की अतिरिक्त लागत का वहन करना है।

(ढ) सामान्य मूल्य:- याचिकाकर्ता ने निर्यात करने वाले देशों के घरेलू बाजार में इस उत्पाद की कीमत के बारे में कोई सूचना अथवा इन देशों के निर्यातक की कीमत सूची नहीं दी है। वह संबद्ध देशों से अन्य देशों (सिंगापुर के अलावा) को निर्यातों के कोई सही और पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके। इसके अतिरिक्त उद्गम देश में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत और स्वीकार्य वृद्धि के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है। इसके बजाए याचिकाकर्ता ने निर्यातित देशों में फेनोल की "परिकलित उत्पादन लागत" की गणना की है और निर्दिष्ट प्राधिकारी इससे स्वीकार करने का अनुरोध किया है। यह निवेदन है कि उत्पादन की ऐसी परिकलित लागत पर आधारित सामान्य मूल्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि इन देशों में प्रौद्योगिकीय विकास अधिक उत्कृष्ट है और इस प्रकार उनके कच्चे माल के खपत संबंधी मानदण्ड विशेष रूप से स्टीम, प्रशीतित पानी, शीतकाकर पानी संपीड़ित हवा इत्यादि जैसी उपयोगिताएं भारत में प्रचलित संयंत्रों से अधिक सुदृढ़ हैं। उनकी जनशक्ति की जरूरत भारत की अपेक्षा बहुत कम है और इन देशों में प्रचलित ब्याज दर भी भारत से काफी कम हैं। इस प्रकार प्रयोक्ताओं का यह कहना है कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों का निर्णय करने के लिए भारतीय मानकों के आधार पर उत्पादन की लागत परिकलित करना उचित नहीं होगा। यह बात भी उठाई गई है कि दक्षिण अफ्रीका के मामले में याचिकाकर्ता विनिर्माण प्रक्रिया से भी अवगत नहीं हैं और इस प्रकार उत्पाद नकी परिकलित लागत की गणना करने की उनकी योग्यता भी संदिग्ध है। निर्यात मूल्य के बारे में याचिकाकर्ताओं ने सिंगापुर से भारत और अन्य देशों को निर्यात से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। यह सूचना स्टेट लिंक द्वारा प्रकाशित एक व्यापार सांख्यिकी पर आधारित है, जो सिंगापुर व्यापार प्राधिकरण का सरकारी प्रकाशन मालूम नहीं होता है।

ण. याचिकाकर्ता ने पुनः डीजीसीआई एण्ड एस और रक्षोपाय महानिदेशालय द्वारा सूचित आयात के आंकड़ों के बीच भिन्नता के बारे में उल्लेख किया है लेकिन जैसाकि हमारे द्वारा पहले बताया गया है, रक्षोपाय महानिदेशालय के आंकड़े फेनॉल विनिर्माताओं द्वारा दी गई बाजार संबंधी सूचना पर आधारित थे जबकि डीजीसीआई एण्ड एस द्वारा प्रकाशित सूचना आयातों के बारे में सही सूचना है।

त. याचिकाकर्ताओं द्वारा उल्लेखित क्षति का एक मुख्य मापदण्ड जांच अवधि के दौरान एचओसीएल की लाभप्रदता में गिरावट आना है। याचिका के पृष्ठ 1 में दी गई तालिका के अनुसार पहले के तीन वर्षों 98-99 से 2000-2001 की तरह अप्रैल, 2001-जून, 01 की तिमाही में लाभ हुआ था लेकिन जुलाई, 2001-सितम्बर, 2001 और अक्टूबर 2001-दिसम्बर, 2001 में घाटा हुआ है। वस्तुतः एचओसी के 1988-89 से 2000-2001 तक के लाभ आंकड़ों के अध्ययन से यह मालूम होता है कि कोच्चि इकाई का लाभ 1997-98 तक की 10 वर्षों की अवधि में 14% से बहुत अधिक बढ़कर 990% हो गया। तत्पश्चात कोच्चि इकाई अब भी लगातार काफी लाभ अर्जित कर रही है और वर्ष 2000-2001 में ***** लाख रुपए लाभ हुआ था।

करोड़ रुपए

वर्ष	रासायनी	कोच्चि	कुल
98-99	-41.24	10.17	-23.07
99-00	-109.92	4.90	-105.02
2000-2001	-80.43	41.37	-39.05

थ. तथापि, यह देखा गया है कि एचओसीएल की अब अंकेक्षित परिणाम के आधार पर लाभ का तिमाही अनुमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर सही साबित नहीं हुआ। इस तरह दिसम्बर, 2001 तक एचओसी द्वारा उठाए गए घाटों के आंकड़ों को इसके संपरीक्षित वित्तीय परिणाम उपलब्ध होने तक स्वीकार करना उचित नहीं होगा।

द. यह ध्यान रखना होगा कि एचओसीएल का फेनोल संयंत्र 12 वर्ष से अधिक पुराना है और इस प्रकार इसका पूर्ण मूल्य ह्रास हो चुका है और आंशिक ऋण देनदारियों से मुक्त है। तथापि यह प्रतीत होता है कि मूल्य ह्रास और ब्याज को लागत संघटकों के रूप में अभी जोड़ा गया है।

ध. याचिकाकर्ताओं की यह अवधारणा कि कोलतार पद्धति से उत्पादन की लागत एचओसीएल द्वारा अपनाई जाने वाली पद्धति से अधिक है, का कोई प्रमाण नहीं है और यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार याचिकाकर्ता द्वारा यथा परिकल्पित उत्पादन की कंस्ट्रक्टेड लागत के संबंध में इसी आधार पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। हमारी सूचना के अनुसार कोलतार आधारित प्रक्रिया से फेनोल की उत्पादन लागत बेंजीन और प्रोपिलीन, जो महंगी पेट्रोलियम आधारित कच्ची सामग्री हैं, की तुलना में कच्चे माल की कम लागत के कारण निश्चित रूप से कम है।

न. संबद्ध देशों से निर्यात कीमतें वर्ष 2000-2001 में जब मुख्य रूप से कच्चे तेल की अत्यधिक कीमत के कारण कच्ची सामग्री की कीमतें बढ़ गई थी, को छोड़कर हमेशा 18000/-रुपए टीपीए से 2100/-रुपए के बीच रही थी। अब कच्चे तेल की कीमतें कम हो गई हैं इसलिए फेनोल का मूल्य पुनः सामान्य हो गया है। इस प्रकार जांच अवधि में सिंगापुर से भारत को आयात किए गए फेनोल के मूल्य का यही रुख चल रहा है।

प. एचओसी के फेनोल संयंत्र की निर्धारित 40,000 टीपीए है। यह देखा गया है कि एचओसीएल पिछले तीन वर्षों में क्षमता का लगभग पूर्ण उपयोग कर रहा था। अप्रैल-दिसम्बर, 2001 के दौरान क्षमता उपयोग 72.5% रही है लेकिन इसका कारण आयातों में वृद्धि नहीं बल्कि एचओसी की आन्तरिक समस्या है।

फ. यह देखा गया है कि उसी अवधि में फेनोल के अन्य विनिर्माता, हरदीलिया कैमिकल्स लि0 (एचसीएल) ने पिछले वर्ष में इसके द्वारा किए गए 29804 मी0 टन के उत्पादन की तुलना में

23928 मी० टन (31904 मी० टन वार्षिक) (7% वृद्धि) का उत्पादन किया। इस प्रकार बाजार के हालात कम उत्पादन के लिए उत्तरदायी नहीं थे परन्तु एचओसीएफ के कम उत्पादन के फलस्वरूप ही देश में फेनोल का आयात हुआ।

घ. प्राधिकारी द्वारा जांच और जांच परिणाम

14. याचिकाकर्त्ताओं, आयातकों, निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्राधिकारी के समक्ष यथा प्रस्तुत कागजातों, की जांच परिणाम पर पहुँचते समय जांच की गई और विचार किया गया और इसके बाद यथोचित स्थान पर उनका उल्लेख किया गया है।

(ii) प्राधिकारी संबद्ध देशों से निर्यातकों से निर्धारित पद्धति और विधि से पूर्ण और पर्याप्त उत्तर के प्राप्त न होने पर उपर्युक्त नियम 6(8) के अनुसार उन्हें उपलब्ध तथ्यों के आधार पर संबद्ध देशों से निर्यात के संबंध में निकाले गए जांच परिणामों की पुष्टि करते हैं।

(iii) नए निर्यातकों अथवा जो निर्यातक कीमत संबंधी वचनपत्र देने के इच्छुक बताए गए हैं उनके मामलों पर प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त नियमों के अनुसार अनुरोध किए जाने पर विचार किया जाना चाहिए।

विचाराधीन उत्पाद एवं समान वस्तु

(i) इस जांच में विचाराधीन उत्पाद फेनोल है जो कार्बोलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। फेनोल के उत्पादन में बेंजीन और एलपीजी दो प्रमुख अपेक्षित निवेश हैं। क्यूमेन का विनिर्माण उच्च दाब और बढ़े हुए तापमान पर ठोस फास्फोरिक एसिड उत्प्रेरक की मौजूदगी में प्रोपिलीन और बेंजीन की प्रतिक्रिया के द्वारा होता है। फेनोल का उत्पादन अधिक ताप और दाब पर वायु का प्रयोग करके क्यूमेन से आक्सीकरण द्वारा किया जाता है। न्यूनतम सान्द्रण पर यह उत्पाद क्यूमेन हाइड्रोपेरोक्साइड है जिसे बाद क्षार मुक्त करके एक अधिक शक्ति तक पर सांद्रित किया जाता है। बाद में इसको एच२ एसओ४ के साथ मिश्रित किया जाता है जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप फेनोल और एसिटोन

बनता है। फेनोल सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय xxix के उपशीर्ष 2907.11 और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय xxvii के अन्तर्गत उपशीर्ष 2707.60 के अन्तर्गत वर्गीकृत एक मूल आर्गेनिक रसायन है। वर्तमान जांच विचाराधीन उत्पाद के संबंध में है चाहे उनका आयात किसी भी वर्गीकरण के अन्तर्गत किया जाता हो। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वह वर्तमान जांच की व्याप्ति पर किसी भी तरह बाध्यकारी नहीं है।

- (ii) पाटनरोधी नियमावली के नियम-2 (घ) में निर्दिष्ट है कि समान वस्तु का अभिप्राय उस वस्तु से है जो जांचाधीन उत्पाद के साथ हर तरह से समरूप और समान हो अथवा ऐसी वस्तु के अभाव में ऐसी अन्य वस्तु से है जिसकी विशेषताएं जांचाधीन वस्तु की विशेषताओं से अत्यधिक मेल खाती हो।
- (iii) याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तु संबद्ध देशों द्वारा उत्पादित अथवा निर्यातित वस्तु के समान वस्तु है। तथापि, कुछ निर्यातकों एवं आयातकों का तर्क है कि उनके द्वारा आयातित फेनोल गुणवत्ता में भिन्न है। तथापि, उनके द्वारा इस बात के कोई साक्ष्य नहीं दिए गए हैं कि आयातित फेनोल देश में उत्पादित फेनोल का तकनीकी अथवा वाणिज्यिक रूप से स्थान नहीं ले रहा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित फेनोल की विशेषताएँ संबद्ध देशों से आयातित फेनोल के समान हैं। इस दृष्टि से प्राधिकारी का मानना है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित फेनोल और संबद्ध देशों से आयात किया जा रहा फेनोल क्षति निर्धारण के प्रयोजनार्थ नियमों के अर्थ के भीतर समान वस्तु है।

न्यूनतम सीमा को पार करना

16. यह पता लगाने के लिए कि जांच अवधि (पीओआई) के दौरान संबद्ध देशों से आयात न्यूनतम स्तर से अधिक रहे हैं, प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के इस तर्क की जांच की कि संबद्ध वस्तु के लिए डीजीसीआई एण्ड एस द्वारा प्रकाशित आंकड़ों को स्वीकार न किया जाए क्योंकि डीजीसीआई एण्ड एस द्वारा प्रकाशित किए गए निर्यात आंकड़े अधूरे हैं और अधिकांश सौदों के

आंकड़ों में सूचित नहीं किया गया है। प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आंकड़े और कांडला पत्तन सीमाशुल्क द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों का आपस में मिलान किया और नोट किया कि पीओआई के लिए डीजीसीआई एण्ड एस के आंकड़े अधूरे हैं और बहुत से आयात विशेषतौर पर दक्षिण अफ्रीका से बल्क आयात और यूरोपीय संघ से आयातों को सही रूप में नहीं दर्शाया गया है। अतः प्राधिकारी ने दक्षिण अफ्रीका (बल्क आयात) और यूरोपीय संघ से आयातों के निर्धारण के लिए कांडला पत्तन सीमाशुल्क आंकड़ों को लिया है और दक्षिण अफ्रीका (ड्रम आयात) और सिंगापुर से निर्यातकों द्वारा किए गए प्रस्तुत निवेदनों का माना है। इस प्रकार प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान संबंध देशों से संबंध वस्तुओं के आयात न्यूनतमस्तर से अधिक है।

देश का नाम	मात्रा (मी. टन) जांच अवधि	आयातों में % हिस्सा (जांच अवधि)
सिंगापुर	* * * *	27.48
दक्षिण अफ्रीका	* * * *	15.84
यूरोपीय संघ	* * * *	31.2

17. घरेलू उद्योग:- यह याचिका घरेलू उद्योग की ओर से एचओसीएल, मुम्बई द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि संबंध वस्तुओं के कुल भारतीय उत्पादन में उनका लगभग 47% हिस्सा है। अनेक निर्यातकों/आयातकों/प्रायोक्ताओं का तर्क है कि याचिकाकर्ता आवेदन करने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) को उद्धृत किया है जिसमें कहा गया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी उपनियम (क) के अन्तर्गत किए गए आवेदन के अनुसार तब तक कोई जांच शुरू नहीं करेगा जब तक कि समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों द्वारा व्यक्त आवेदन के समर्थन अथवा विरोध की सीमा की जांच के आधार पर निर्धारण न कर ले कि आवेदन घरेलू उद्योग के द्वारा या उसकी ओर से किया गया है परन्तु यह इस शर्त के अध्वधीन है कि आवेदन का स्पष्ट रूप से समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादकों का समान वस्तु के कुल उत्पादन में 25% से कम हिस्सा हो तो कोई जांच शुरू नहीं की जाएगी। उप-नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आवेदन को घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से प्रस्तुत किया गया तब माना जाएगा जब इसका समर्थन उन घरेलू उत्पादकों द्वारा किया गया हो जिनका सामूहिक उत्पादन

उक्त आवेदन का समर्थन अथवा विरोध करने वाले घरेलू उद्योग के उस भाग द्वारा उत्पादित समान उत्पाद के कुल उत्पादन के 50% से अधिक हो।

18. प्राधिकारी ने रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्यों के साथ ही इस संबंध में आयातकों/उपयोगकर्ताओं/निर्यातकों द्वारा दिए गए तर्क की जांच की है। यह मालूम होता है कि इस देश में मे0 हरदीलिया कैमिकल्स लि0 (एचसीएल) फेनोल का एक अन्य मुख्य उत्पादक है और उसने एचओसीएल द्वारा दायर याचिका का समर्थन किया है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हरदीलिया कैमिकल्स लि0 ने संबंध देशों से जांच अवधि के दौरान संबंध वस्तुओं का आयात किया है और इस प्रकार उसे घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं माना जा सकता और इसलिए प्राधिकारी ने उसे आगे की जांच में छोड़ दिया है। हरदीलिया कैमिकल्स को छोड़कर घरेलू उद्योग अवस्थिति के मानदंड को पूरा करता है।

इस प्रकार प्राधिकारी इस बात पर कायम है कि याचिकाकर्ता प्रारंभिक जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त नियमों के नियम (3) (क) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से याचिका दायर करने की स्थिति का मानदण्ड पूरा करते हैं। प्राधिकारी इन याचिकाकर्ता कंपनियों को भी उपर्युक्त नियम 2(ख) के अर्थों के भीतर घरेलू उद्योग के रूप में मानते हैं।

(ड.) पाटन और सामान्य मूल्य और निर्यात कीमतों के संबंध में किए गए दावों की जांच

सामान्य मूल्य

19. सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम 1995 की धारा 9क (1) (ग) के अन्तर्गत किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का अभिप्राय:-

- (i) सामान्य व्यापार के दौरान समान वस्तुओं के लिए उप-धारा (6) के अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार यथानिश्चित तुलनात्मक मूल्य से है जबकि ऐसी वस्तु निर्यातक देश या क्षेत्र में उपभोग के लिए अभिप्रेत हो, या
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के स्वदेशी बाजार में सामान्य व्यापार के दौरान समान वस्तु की कोई बिक्री नहीं हो या बाजार की विशेष स्थिति के कारण अथवा निर्यातक देश या क्षेत्र के स्वदेशी बाजार में बिक्री की कम मात्रा के कारण, ऐसी बिक्रियों की समुचित तुलना

- (क) निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से आयात किये जाने पर समान वस्तु का उपधारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथानिश्चित तुलनात्मक सादृश्य मूल्य; अथवा
- (ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथानिश्चित, प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य मूल्य एवं लाभों के लिए उचित वृद्धि के साथ-साथ उद्गम देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत से हैं-

20. प्राधिकारी ने धारा 9क (1)(ग) के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के प्रयोजन से सभी ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी थीं । प्राधिकारी को निम्नलिखित निर्यातकों तथा निर्यातक एसोसिएशन से उत्तर प्राप्त हुए:-

1. मित्सुई एंड कं० लि०, सिंगापुर ब्रांच
2. मित्सुई फिनोल सिंगापुर लि० (एमपीएसएल), सिंगापुर
3. मेरीसोल आरएसए (पीटीवाई) लि०, दक्षिण अफ्रीका

21. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै० मित्सुई एंड कम्पनी लि० जापान में निगमित तथा सूचीबद्ध एक सरकारी कम्पनी है । जांच की अवधि के दौरान उन्होंने भारत में भिन्न-भिन्न कम्पनियों को निर्यात किया है यद्यपि उनकी घरेलू बिक्रियां नहीं होती हैं । दूसरी ओर, मै० मित्सुई फिनोल सिंगापुर पीटीई लि०, सिंगापुर ने जांच की अवधि के दौरान भारत को व्यापारिक घरानों के माध्यम से निर्यात किए थे और इस अवधि में उन्होंने घरेलू बिक्रियां भी की थी ।

सिंगापुर के लिए सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत का निर्धारण

22. सिंगापुर के निर्यातकों में से केवल मै० मित्सुई एंड कम्पनी लि०, सिंगापुर ब्रांच तथा मै० मित्सुई फिनोल सिंगापुर लि० ने उत्तर दिया था । मै० मित्सुई फिनोल सिंगापुर पीटीई लि० ने घरेलू बाजार में की गई बिक्रियों के सम्बन्ध में सूचना दी है और उन्होंने परिशिष्ट-1 के अनुसार बीजकों की संख्या तथा तारीखों के साथ-साथ बेची गई मात्राओं का भी लेखा-जोखा दिया है । उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने व्यापारिक घरानों के माध्यम से भारत में फिनोल की बिक्री की है और उन्होंने किए गए लदान सम्बन्धी व्यौरों के साथ-साथ ग्राहकों के नाम तथा पते भी दिए । तथापि, उन्होंने

अपने अनुरोधों में पिछले तीन वर्षों के कोई भी लाभ तथा हानि के विवरण तथा तुलन पत्रों को संलग्न नहीं किया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि निर्यातक ने प्रश्नावली के दिए गए अपने उत्तर के अनुसार अपने अनुरोधों में परिशिष्ट 8, 9 तथा 10 में यथापेक्षित वित्त पोषण और ब्याज लागत के बारे में कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है।

तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि परिशिष्ट-1 में बीजक, संख्या तारीख बिक्री की गई मात्रा तथा प्रति इकाई दर देते हुए घरेलू बिक्रियों के बारे में अलग-अलग सौदे प्रस्तुत किए हैं जिससे यह पता चलता है कि उनकी बिक्रियां व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में की गई हैं। निर्यातक ने परिशिष्ट-3 के बारे में भी सूचना प्रस्तुत की, जिससे भारत को निर्यात तथा घरेलू बाजार की बिक्रियों का पता चलता है। उन्होंने परिशिष्ट-4 और 5 भी प्रस्तुत की है जिससे भारत को हुए निर्यातों के लिए कीमत ढांचे तथा घरेलू बिक्रियों के लिए बिक्री कीमत ढांचे का पता चलता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने परिशिष्ट 8 और 9 के अनुसार वित्तीय तथा ब्याज लागतों को छोड़कर मुख्य शीर्षों के तहत सूचना प्रस्तुत की है जिसमें घरेलू बिक्रियों तथा भारत को हुए निर्यात की बिक्री कीमत के लिए कारखाना द्वार पर कीमत दी गई है। प्रारंभिक निर्धारण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी भारत औसत आधार पर घरेलू बिक्री हेतु कारखाना-द्वार पर कीमत को सामान्य मूल्य के रूप में लेकर तथा भारत औसत आधार पर ही भारत को की गई बिक्रियों की कारखानाद्वार पर कीमत को निर्यात कीमत के रूप में लेकर सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत का निर्धारित करने के लिए निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों को स्वीकार करते हैं जो आगे सत्यापन तथा जांच के अधीन हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक ने घरेलू बाजार में *** अमरीकी डालर की *** मी. टन की बिक्री की है और परिशिष्ट-5 के अनुसार कमीशनों, भाड़े आदि के लिए समायोजन करने के बाद कारखाना द्वार पर कीमत *** अमरीकी डालर बैठती है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की अवधि में फर्म ने *** अमरीकी डालर दर से *** मी0 टन का निर्यात किया है और सभी समायोजनों के बाद कारखाना द्वार पर कीमत *** अमरीकी डालर बैठती है। पाटनरोधी करार के अनुसार सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमतों की तुलना उसी स्तर पर अधिमानतः कारखाना द्वार स्तर पर की जानी चाहिए। तथापि, चूंकि सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत को कारखाना द्वार पर लिया गया है, इसलिए इन मूल्यों में आगे और समायोजन किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य

*** अमरीकी डालर के रूप में तथा निर्यात कीमत *** अमरीकी डालर के रूप में निर्धारित की है। तदनुसार, पाटन मार्जिन ** अमरीकी डालर अथवा निर्यात कीमत का 28.75% बैठता है।

मै0 मित्सुई एंड कम्पनी लि0, सिंगापुर ब्रांच ने मै0 मित्सुई फिनोल पीटीई लि0 द्वारा दिए गए तर्कों के समान ही तर्क दिए हैं। उन्होंने प्रश्नावली की परिशिष्ट-I के अनुसार कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है। तथापि परिशिष्ट-III के अनुसार उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने घरेलू बाजार में कोई बिक्री नहीं की है। उन्होंने ग्राहकों के नाम और पतों के साथ-साथ किए गए पोत लदानों के ब्यौरे देते हुए भारत को किए गए निर्यातों का ब्यौरा भी दिया है। उन्होंने भारत तथा भारत से भिन्न देशों को किए गए निर्यातों की बिक्री कीमत ढाचे के बारे में भी सूचना प्रस्तुत की है। उन्होंने छूटों/कमीशनों तथा विदेशी भाड़े के लिए समायोजन करने के बाद भारत को किए गए निर्यातों की कारखाना द्वार पर कीमत का परिकलन किया है तथापि उनके पास परिशिष्ट- vi से आगे कोई भी सूचना नहीं है अतः प्राधिकारी निर्यातक द्वारा किए गए अनुरोधों को पूर्ण रूप से मानने को बाध्य हैं तथापि प्राधिकारी ने सत्यापन तथा जांच की शर्त के अधीन निर्यातक के अनुरोधों को स्वीकार किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच की अवधि के दौरान फर्म ने सम्बद्ध वस्तु का कुल *** अमरीकी डालर के मूल्य का *** मी. टन का भारत को निर्यात किया और कारखाना द्वार पर उनकी निर्यात कीमत छूटों/कमीशनों तथा विदेशी भाड़े को समायोजन करने के बाद *** अमरीकी डालर मानी गई है। फर्म ने दावा किया है कि उन्होंने तीसरे देश को निर्यात किए हैं और जांच की अवधि के दौरान तीसरे देश को की गई बिक्रियों का लेखाजोखा प्रस्तुत किया है। तथापि, प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना होने के कारण और चूँकि दोनों निर्यातक उसी देश के हैं, जिसकी कीमतें बाजारी शक्तियों द्वारा निर्धारित होती हैं। पूर्ववर्ती पैराग्राफ में किए गए उल्लेख के अनुसार मै0 मित्सुई फिनाल सिंगापुर पीटीई लि0 हेतु उपलब्ध किए गए आंकड़ों का हवाला देते हुए मित्सुई एण्ड कं. की घरेलू बिक्री कीमत ली है। अतः, प्राधिकारी मित्सुई एंड कं. लि. के लिए सामान्य मूल्य ** अमरीकी डालर लिया है। चूँकि निर्यातक ने परिशिष्ट- vii से संबंधित और उससे आगे कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है इसलिए सामान्य मूल्य की गणना में मै0 मित्सुई एण्ड कं0 को कोई निर्यात विशिष्ट समायोजन प्रदान नहीं किया

जा सकता । मै0 मित्सुई एंड कम्पनी के लिए पाटन मार्जिन ** अमरीकी डालर या निर्यात कीमत का % बैठता है ।

सिंगापुर के अन्य निर्यातक

23. जहाँ तक अ-सहयोगी निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण का सम्बंध है, प्राधिकारी ने वही सामान्य मूल्य लिया है जैसाकि मै. मित्सुई एण्ड कं. के मामले में पूर्ववर्ती पैराग्राफ में निर्धारित किया गया है । कमीशन, समुद्री भाड़े और बीमा के लिए समायोजन करने के बाद कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत निकाली गई है । प्राधिकारी ने अ-सहयोगी निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य ** अमरीकी डालर तथा निर्यात कीमत ** अमरीकी डालर निर्धारित की है । अ-सहयोगी निर्यातकों के लिए पाटनमार्जिन ** अमरीकी डालर अथवा निर्यात कीमत का 41.47% बैठता है ।

मेरीसोल आरएसए (पीटीवाई), दक्षिण अफ्रीका के लिए सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत

24. मै0 मेरीसोल आरएसए (पीटीवाई), दक्षिण अफ्रीका ने प्रश्नावली का उत्तर दिया है परन्तु भिन्न-भिन्न अनुबंधों के बारे में उन्होंने अपूर्ण सूचना दी है । परिशिष्ट-1 के अनुसार उन्होंने बीजक संख्या बेची गई मात्रा, बिक्री मूल्य तथा प्रति इकाई दर का उल्लेख करते हुए अपने घरेलू बाजार में की गई विभिन्न बिक्रियों के बारे में विस्तृत सूचना प्रस्तुत की है । उन्होंने दो प्रमुख ग्रेडों, ड्रम बिक्रियों तथा बल्क बिक्रियों के बारे में मात्रा तथा प्रति इकाई दर के साथ अपनी घरेलू बिक्रियों की बीजक संख्याएं भी दी हैं । परिशिष्ट-2 में उन्होंने जांच की अवधि के लिए भारत को फिनोल के निर्यातों का लेखा भी प्रस्तुत किया है । उन्होंने भारतीय ग्राहकों के नाम से बिक्री के लेखे देते हुए सूचना का समर्थन किया जिसमें बीजक मूल्यों समुद्री भाड़ों, बीमा, कमीशन आदि का ब्यौरा दिया गया है । परिशिष्ट-3 में उन्होंने भारत को हुए निर्यात, तीसरे देशों को हुई बिक्रियों तथा अपने घरेलू बाजारों में हुई बिक्री का लेखा जोखा दिया है । उन्होंने भारत को हुए निर्यात के लिए बिक्री कीमत ढांचे तथा घरेलू बिक्रियों के लिए बिक्री कीमत ढांचो का उल्लेख करते हुए परिशिष्ट-4 और 5 प्रस्तुत की है । तथापि उन्होंने अपने अन्य उत्पाद की मात्रा तथा मूल्य के बारे में पर्याप्त सूचना प्रस्तुत नहीं की । तथापि उन्होंने कारखाना लागत तथा भारत को हुए निर्यात के लाभों और अपनी बल्क और ड्रम बिक्रियों के बारे में उनके घरेलू बाजारों का भी लेखा प्रस्तुत किया यद्यपि उन्होंने

अपनी वित्तीय व्यवस्था तथा ब्याज लागतों के बारे में अपेक्षित सूचना प्रस्तुत नहीं की है और उन्होंने निवल लाभ भी प्रस्तुत नहीं किया है जिसे उन्होंने परिशिष्ट-8 और 9 में अपनी कारखाना द्वार पर लागतों में जोड़ दिया है। प्राधिकारी ने निर्यातक के अनुरोधों की छान-बीन की है और प्रारंभिक जांच परिणामों के सीमित प्रयोजन के लिए निर्यातक के अनुरोधों को स्वीकार करने के इच्छुक है जो आगे और सत्यापन तथा जांच के अधीन है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि में अपने बाजार में मेरीसौल एस ए ने *** अमरीकी डालर की ** मी० टन की बल्क बिक्री की और ** अमरीकी डालर की ** मी० टन की ड्रम बिक्री की है। प्राधिकारी ने निर्यातक द्वारा प्रस्तुत अंतर्देशीय भाड़ा, बीमा, भंडारण तथा हैंडलिंग लागत का समायोजन करने के बाद घरेलू बाजार में कारखाना द्वारा पर कीमत के रूप में ** अमरीकी डालर और ** अमरीकी डालर (क्रमशः बल्क तथा ड्रम) के सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है जैसाकि निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। चूंकि यह सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत कारखाना द्वार पर ली गई हैं, इसलिए इन मूल्यों में और अधिक समायोजन किए जाने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक निर्यात कीमत के निर्धारण का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक ने सम्बद्ध वस्तु की भारात को हुई बल्क बिक्रियों के लिए ** अमरीकी डालर की दर पर ** अमरीकी डालर मूल्य के ** मी० टन का तथा ड्रम बिक्रियों के लिए ** अमरीकी डालर की दर पर ** अमरीकी डालर मूल्य के ** मी० टन का निर्यात किया है। इस प्रकार स्वदेशी भाड़े, हैंडलिंग, बीमा, विदेशी भाड़े, विदेशी कमीशन आदि का समायोजन करने के बाद कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत निर्धारित की गई है जैसा कि निर्यातक ने अनुमान लगाया था और इस प्रकार बल्क बिक्रियों के लिए ** अमरीकी डालर और ड्रम बिक्रियों के लिए ** अमरीकी डालर की निर्यात कीमत आंकी गई है।

पाटनरोधी करार के अनुसार सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमतों की तुलना उसी स्तर पर अधिमानतः कारखाना द्वार स्तर पर की जानी चाहिए। तथापि चूंकि सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत कारखानाद्वार स्तर पर ली गई है, इसलिए इन मूल्यों में और अधिक समायोजन किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है और पाटन मार्जिन बल्क बिक्रियों के लिए ** अमरीकी डालर या निर्यात कीमत का 42.24 % और ड्रम बिक्रियों के लिए ** अमरीकी डालर या निर्यात कीमत का 36.48% बैठता है।

दक्षिण अफ्रीका के अन्य निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत

25. जहां तक अ-सहयोगी निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण का संबंध है, प्राधिकारी ने बल्क बिक्रियों तथा ड्रम बिक्रियों के लिए कारखाना द्वार पर भारित औसत घरेलू बिक्री कीमत के रूप में सामान्य मूल्य को लिया है।

जहां तक निर्यात कीमत का संबंध है प्राधिकारी बल्क तथा ड्रम दोनों बिक्रियों के लिए अ-सहयोगी निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत के रूप में जांच की अवधि के दौरान दक्षिण अफ्रीका से भारत को हुए निर्यात की न्यूनतम कीमत को लिया है। तथापि चूंकि इन सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को कारखाना द्वारा स्तर पर लिया गया है, इसलिए इन मूल्यों में आगे और समायोजन किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्राधिकारी ने बल्क तथा ड्रम बिक्रियों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण क्रमशः ** अमरीकी डालर तथा ** अमरीकी डालर किया है तथा अ-सहयोगी निर्यातकों के लिए बल्क तथा ड्रम दोनों बिक्रियों के लिए ** अमरीकी डालर और ** अमरीकी डालर की निर्यात कीमत निर्धारित की है। इस प्रकार बल्क और ड्रम बिक्रियों के लिए पाटन मार्जिन क्रमशः ** अमरीकी डालर या निर्यात कीमत का 101.32% तथा ** अमरीकी डालर या निर्यात कीमत का 62.40% बैठता है।

यूरोपीय संघ के लिए सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत

26. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यूरोपीय संघ के किसी भी निर्यातक ने कोई उत्तर नहीं दिया है। चूंकि सम्बद्ध वस्तु के घरेलू बिक्री कीमत ढांचे, यूरोपीय संघ में इसकी उत्पादन के बारे में कोई सूचना और प्रश्नावली के अनुसार कोई अन्य सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है, इसलिए प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना पर निर्भर रह कर कार्रवाई शुरू की है। याचिकाकर्त्ताओं ने उत्पादन की परिकलित लागत के आधार पर यूरोपीय संघ के बारे में सामान्य मूल्य का दावा किया है। प्राधिकारी ने पाया है कि किसी भी निर्यातक ने घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है। प्राधिकारी सम्बद्ध देशों के निर्यातकों से निर्धारित प्रपत्र में तथा ढंग से किसी सूचना के अभाव में उपरोक्त नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सम्बद्ध देशों से हुए निर्यातों के बारे में निकाले गए जांच परिणामों की पुष्टि करते हैं।

तदनुसार, प्राधिकारी ने लागू समायोजनों के साथ याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध किए गए उत्पादन लागत संबंधी आंकड़ों के आधार पर सामान्य मूल्य का परिकलन किया है। ई0यू0 के लिए इस प्रकार से निर्धारित किया गया सामान्य मूल्य *** अमरीकी डालर बनता है।

याचिकाकर्ता ने यूरोपीय संघ से सम्बद्ध वस्तु के आयातों के बारे में सूचना प्रस्तुत की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यूरोपीय संघ ने *** अमरीकी डालर की दर पर *** अमरीकी डालर मूल्य के *** मी0 टन का निर्यात किया है। प्राधिकारी ने जांच की अवधि के लिए डीजीसीआई एण्ड एस के आंकड़ों के आधार पर यूरोपीय संघ से भारत को हुए निर्यात की कीमत निकाली है तथा समुद्री भाड़े, विदेशी बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय, स्वदेशी भाड़े के लिए समायोजनकरनें के बाद कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत *** अमरीकी डालर बैठती है। पाटन मार्जिन ** अमरीकी डालर बैठती है। पाटन मार्जिन *** अमरीकी डालर या निर्यात कीमत का 97.72% बनता है।

	देश	पाटन मार्जिन
1.	यूरोपीय संघ	97.72
2.	सिंगापुर	
	मित्सुई एंड कं0	28.50
	मित्सुई पि०नॉल	28.76
	सिंगापुर लि0	
	अन्य निर्यातक	53.42
3.	दक्षिण अफ्रीका	
	मेरीसोल, आरएसए	
	बल्क बिक्रियां	42.24
	अन्य बल्क बिक्रियां	101.32
	मै0 मेरीसोल आरएसए	
	ड्रम बिक्रियां	36.48
	ड्रम बिक्रिया (अन्य)	62.40

(च) क्षति

27. पाटनरोधी नियमावली का नियम-11 निम्नानुसार है:

“क्षति का निर्धारण :

(i) विनिर्दिष्ट देशों से हुए आयातों के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी आगे इस आशय का आपना जाच परिणाम दर्ज करेंगे कि भारत में होने वाले ऐसे आयातों से भारत में स्थापित किसी उद्योग को वास्तविक क्षति होती है अथवा क्षति का खतरा उत्पन्न होता है अथवा किसी उद्योग को स्थापित करने में बाधा आती है ।

(ii) निर्दिष्ट प्राधिकारी घरेलू उद्योग को हुई क्षति, घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के खतरे, घरेलू उद्योग की स्थापना में आने वाली वास्तविक बाधा और पाटित आयातों की मात्रा और समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर इसके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों को परिणामी प्रभाव समेत सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और इन नियमों के अनुबंध-11 में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार पाटित आयातों और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का मूल्यांकन करेंगे ।

(ii) क्षति के निर्धारण हेतु पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-11 में यह सिद्धांत निर्धारित किया गया है कि:-

(क) क्षति के निर्धारण में (क) पाटित आयातों की मात्रा तथा समान वस्तु के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव तथा (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव दोनों की वस्तुपरक जांच शामिल होगी ।

(ख) पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय उक्त प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन अथवा खपत की तुलना में काफी वृद्धि हुई है । नियम 18 के उप नियम (2) में यथा उल्लिखित कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा काफी हद तक कीमतों में कमी लाना अथवा कीमत में उस वृद्धि को रोकना है जो कि अन्यथा काफी हद तक बढ़ गई होती ।

४. याचिकाकर्ता के विचार

घरेलू उद्योग को दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर तथा यूरोपीय संघ से फिनाल के पाटन से हानि हो रही है। पाटनरोधी नियम के अनुबंध 2(2) में यह प्रावधान है कि यदि एक से अधिक देशों से किसी उत्पाद के आयात की जांच एक साथ की जा रही हो तो निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन करेंगे, यदि वह निर्धारित यह करते हैं कि:-

(क) प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में प्रमाणित पाटन मार्जिन, निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त 2 % से अधिक है तथा प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा समान वस्तु के आयातों की 3 प्रतिशत है अथवा जहां अलग-अलग देश का निर्यात 3 % से कम है, वहां आयात संचयी आधार पर समान वस्तु के आयातों के 7 % से अधिक बनता है, तथा

(ख) आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण आयातित वस्तुओं तथा समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित है।

(ग) प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन का मार्जिन ऊपर निर्धारित सीमा (न्यूनतम) से अधिक है।

(घ) आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण उचित है क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यात भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित कीमतों से सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं। अतः प्राधिकारी है कि वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निर्धारण संबद्ध देश से संचयी आधार पर करें।

(ङ.) संबद्ध देशों से आयातों में समग्र रूप से पर्याप्त वृद्धि हुई है तथा संबद्ध देशों से आयातों के बाजार हिस्से में भी वृद्धि हुई है।

(च) रक्षोपाय शुल्क लगाने के बावजूद आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है। स्पष्ट रूप से, रक्षोपाय शुल्क आयातकों के लिए निवारक साबित नहीं हुआ है। संबद्ध देश से निर्यात की कीमत में महत्वपूर्ण गिरावट आई है तथा अमरीकी डालर में निर्यात कीमत में गिरावट भारतीय रुपयों की तुलना में बहुत ज्यादा है। वस्तुतः कीमत संबद्ध वस्तु के आयातों के पहुंच मूल्य से कम हुई है जो कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम है।

(छ) घरेलू उद्योग की उत्पादन तथा क्षमता उपयोग में नीचे सारणी के अनुसार चालू वर्ष में भारी कमी आई है। अतः संबद्ध देशों से पाटन के कारण घरेलू उद्योग को अपना उत्पादन सीमित करने के लिए बाध्य किया गया है।

(ज) जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में वृद्धि हुई है लेकिन कीमतों में उक्त वृद्धि, कच्चे माल एवं ईंधन की लागत में हुई वृद्धि के कारण, लागत में हुई वृद्धि से कम थी। तथापि, जब आयातित फिनाँल की कीमतों को लागत में हुई वृद्धि में समायोजित किया जाता है तो यह वास्तविक रूप से वर्ष 1998-99 के न्यूनतम स्तर से भी नीचे आ जाती है। इस प्रकार, जहाँ लागत वृद्धि को समायोजित किया गया है, वहीं घरेलू उद्योग की बिक्री प्राप्ति से कमी आई है।

(झ) वह कीमत जिस पर भारत में सामग्री का निर्यात किया जा रहा है, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम नहीं है लेकिन उससे याचिकाकर्ता को पूरी उत्पादन लागत प्राप्त नहीं हो रही है और इसलिए आयात से बाजार में अत्यधिक कीमत कटोती, कमी, कीमतह्रास हो रहा है।

(ग) घरेलू उद्योग फिनाँल आयात करने वाले व्यापारियों के पक्ष में अपने नियमित ग्राहकों से महत्वपूर्ण बिक्रियां गंवा रहा है।

(ट) यद्यपि याचिकाकर्ता की कंपनियों में रोजगार स्तर में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। तथापि, देश में श्रम से संबंधित विधान के कारण छंटनी वस्तुतः असंभव है।

(ठ) फिनाँल की बिक्री जिस कीमत पर हुई है वह उत्पादन लागत और उचित बिक्री कीमत से बहुत कम है, जिसके कारण घरेलू उद्योग को भारी घाटा हुआ है तथा घरेलू उद्योग को उस कीमत पर बिक्री करने के लिए बाध्य किया गया है जिससे उत्पादन की पूरी लागत प्राप्त नहीं हो सकती, लाभ की तो बात ही छोड़ दें।

(ड) घरेलू उद्योग को क्षति सीधे तौर पर संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण हो रही है।

निर्यातकों, आयातकों तथा उपयोगकर्ताओं/एसोसिएशनों के विचार

29. देश में फिनाल के केवल दो विनिर्माता हैं जिनके नाम हैं एचओसीएल तथा एचसीएल जिनका उत्पादन देश में स्थापित कुल क्षमता का 98 % बनेता है। यह देखा जाता है कि एचओसी तथा एचसीएल संयुक्त रूप से फिनाँल की कीमतें बढ़ा रहे थे। इसके अतिरिक्त, यह भी स्पष्ट है कि एचओसीएल तथा एचसीएल दोनों ही पिछले कई वर्षों से समान कीमत वसूल रहे हैं तथा दोनों कंपनियों द्वारा कीमतों में वृद्धि अथवा कमी एक ही तिथि से साथ-साथ की जा रही है। आगे यह देखा जा सकता है कि एचसीएल ने 31 दिसम्बर, 2001 को समाप्त चालू वर्ष के 3 तिमाहियों में उसी कीमत पर लाभ कमाया, जबकि एचओसी दावा करता है इस अवधि में उसने फिनाँल पर

घाटा उठाया है। इस बात को अनुभव किया जाएगा कि किसी एक कंपनी को इतना भारी घाटा तथा दूसरी कंपनी को लाभ हो सकता है जबकि दोनों ही कंपनियां अपने उत्पाद समान बाजार दर पर बेच रही हों।

(क) एचओसी ने बताया था कि इसने महानिदेशालय (रक्षोपाय) के समक्ष की गई वचनबद्धता के अनुसार समायोजन योजना के एक भाग के रूप में लागत कमी की योजना को क्रियान्वित किया है। महानिदेशालय (रक्षोपाय) के जांच परिणामों से यह देखा जाता है कि फिर्नाल विनिर्माताओं ने रक्षोपाय शुल्क के लिए अपने प्रथम आवेदन में रु० 6000 प्रति मी० टन की लागत कमी प्राप्त करने का वायदा किया था तथा जब इसे अगले 2 वर्षों के लिए बढ़ाने की मांग की गई थी, तब एचओसी ने अतिरिक्त रु० 3726 प्रति मी० टन की लागत बचत का वचन दिया था। इस प्रकार 9726 रुपये प्रति मी० टन की लागत बचत प्राप्त करने की योजना थी। फिर्नाल के 40,000 टीपीए के उत्पादन पर ऐसी लागत बचत के कारण आय में कुल वृद्धि 36.34 करोड़ रु० प्रति वर्ष की बनती है। इसके अतिरिक्त एचओसी ने एसीटोन (फिर्नाल का सह उत्पाद) के मामले में 7467 रु० प्रति मी० टन की लागत कटौती (अनुबंध-17) करने का वचन दिया था जिसका अर्थ है 24000 मी० टन की निर्धारित क्षमता के लिए 17.92 रु० की बचत। इस प्रकार फिर्नाल की कीमतों में पर्याप्त कमी की गई होनी चाहिए। तथापि यह देखा जाता है कि जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है वर्ष 2000-01 में फिर्नाल की कुल बिक्री प्राप्ति में 44 % की वास्तविक वृद्धि हुई। इस प्रकार लागत में कमी का लाभ फिर्नाल के ग्राहकों को नहीं मिला, जिसके परिणामस्वरूप देश में फिर्नाल के आयातों में वृद्धि हुई।

(ख) यद्यपि रक्षोपाय शुल्क जुलाई, 01 से 15 % से घटाकर 10 % कर दिया गया है तथापि यह नोट किया जाता है कि रक्षोपाय शुल्क फिर्नाल विनिर्माताओं द्वारा लागत कमी प्राप्त करने तथा रक्षोपाय शुल्क को खत्म करने के लिए दी गई वचनबद्धता के आधार पर मूल रूप से मात्र 2 वर्षों के लिए स्वीकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त रक्षोपाय शुल्क की उक्त घटी दर पर फिर्नाल विनिर्माताओं द्वारा प्राप्त की जा रही शुल्क सुरक्षा 35 % (मूल 25 % + रक्षोपाय शुल्क 10 %) है जो कि वर्तमान शुल्क प्रणाली में बहुत अधिक है। यह भी नोट किया जाता है कि भारतीय रुपयों में यू.एस.डी. दर जून, 99 में 42.95 रु० से बढ़कर वर्तमान में 48.72 हो गयी है, जिसके

परिणामस्वरूप आयात शुल्क में 13.43 % की अतिरिक्त सुरक्षा प्राप्त हुई जिसका कोई इरादा नहीं था ।

(ग) यह देखा जाता है कि एचओसी ने वर्ष 2000-01 में बहुत अधिक लाभ कमाया था जो कि वर्ष 1998-99 में प्राप्त लाभ का 192 % तथा पिछले वर्ष में प्राप्त लाभ का 215 % बनता था । स्पष्ट रूप से एचओसी ने रक्षोपाय शुल्क सुरक्षा का उपयोग किया तथा इसकी एचसीएल के साथ कीमतों को अति उच्च स्तर तक बढ़ाने हेतु संयुक्त विपणन कार्यनीति ने फिर्नाल उपयोगकर्ता उद्योग का प्रचालन लागत इस सीमा तक प्रभावित की कि बेकलाइट हाइलम जैसे फिर्नाल उपयोगकर्ताओं ने अपना परिचालन ही बंद कर दिया है । वस्तुतः 2 वर्षों के लिए रक्षोपाय शुल्क को लगाये जाने तथा इसकी अवधि अगले 2 वर्षों के लिए बढ़ाए जाने का भारत में फिर्नाल उपयोगकर्ता द्वारा भारी विरोध किया गया था तथा महानिदेशालय (रक्षोपाय) की जानकारी में यह लाया गया था कि ऐसी सुरक्षा का उपयोग फिर्नाल आधारित उद्योग की कीमत पर फिर्नाल विनिर्माताओं द्वारा अपने अन्य उत्पाद क्षेत्रों में हुए घाटे को पूरा करने के लिए किया जाएगा ।

(छ) प्राधिकारी द्वारा जांच

30. घरेलू उद्योग को हुई क्षति का विश्लेषण रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर किया गया है तथा पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय के अधिकारी के द्वारा किए गए घरेलू उद्योग की क्षति के निर्धारण हेतु निम्नलिखित मापदंडों का विश्लेषण किया गया है ।

बिक्रियों की मात्रा तथा मूल्य

प्राधिकारी यह पाते हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में बिक्रियों की मात्रा में तथा बिक्रियों के मूल्य में कमी आई है । पिछले वर्षों की तुलना में जांच अवधि में यूनिट कीमत प्राप्ति में भी लगभग 26 % की गिरावट आई है ।

पाटित आयातों की मात्रा तथा बाजार हिस्सा

31. प्राधिकारी ने जांच अवधि तथा पिछले वर्षों के दौरान संबद्ध देशों से निर्यातों की मात्रा के संबंध में सूचना की जांच की है । जांच अवधि के दौरान तीनों संबद्ध देशों से संयुक्त आयात सभी देशों से हुए *** मी0 टन के आयातों की तुलना में ***मी0 टन के हुए थे । वर्ष 2000-01 के दौरान संबद्ध देशों से आयात देश में हुए 14298 मी0 टन के कुल आयातों में से 4501 मी0 टन के

हुए थे । प्रतिशत के संबंध में संबद्ध देशों से हुए आयातों का बाजार हिस्सा 1999-2000 में 64.3%, वर्ष 2000-01 में 31.48% तथा जांच अवधि के दौरान 79.43 % रहा था । पिछले वर्ष 2000-01 की तुलना में जांच अवधि के दौरान बाजार हिस्से में महत्वपूर्ण वृद्धि प्रदर्शित हुई है । मात्रात्मक रूप में भी, जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से हुए आयातों में पिछले वर्ष में हुए आयातों की तुलना में 332 % की वृद्धि प्रदर्शित हुई । बाजार हिस्से में वृद्धि बहुत अधिक है तथा आयातों में वृद्धि समग्र रूप से घरेलू उद्योग के लिए खतरा उत्पन्न करती है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटित आयातों में समग्र रूप से महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है ।

देश	यूरोपीय संघ		सिंगापुर		दक्षिण अफ्रीका	
वर्ष	मात्रा मी०टन	% हिस्सा	मात्रा मी०टन	% हिस्सा	मात्रा मी०टन	% हिस्सा
2000-01	***	11.05	***	0.58	***	3.34
जांच अवधि(9महीने)	***	26.58	***	40	***	13
जांच अवधि वार्षिक	***	26.58	***	40	***	13

संबद्ध देशों से हुए आयातों का बाजार हिस्सा			
वर्ष	संबद्ध देशों से आयात मी० टन	कुल आयात मी० टन	% हिस्सा
1999-2000	18730	29128	64.3
2000-2001	3502	14298	31.48
जांच अवधि वार्षिक	***	***	***

32. संबद्ध देशों से हुए आयातों का बाजार हिस्सा (कुल मांग का%)

प्राधिकारी ने कुल आयातों को घरेलू उद्योग तथा विचराधीन उत्पाद के अन्य उत्पादकों की बिक्रियों के साथ जोड़कर देश में कुल मांग की गणना की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से आयात 9 महीने की अल्प अवधि में कुल मांग का 40 % बाजार हिस्सा हासिल कर सकते हैं।

वर्ष	संबद्ध देशों से हुए आयात मी० टन	कुल आयात मी० टन	% हिस्सा
1999-2000	18730	98764	22.92
2000-2001	4502	81691	5.51
जांच की अवधि वार्षिक	***	***	40.59

उत्पादन तथा कम उपयोग क्षमता

33. निर्यातकों द्वारा यह कहा गया है कि देश में संबद्ध वस्तु की मांग में तेजी से वृद्धि हुई है तथा आयातों में वृद्धि संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादन में आई कमी के कारण हुई है। तथापि घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि उभरते हुए बाजार की मौजूदगी के बावजूद संबद्ध देशों द्वारा अंधाधुंध पाटन के कारण उनके घाटे में वृद्धि हुई है। प्राधिकारी यह पाते हैं कि जांच अवधि में घरेलू उपयोग की क्षमता बिगड़ी है तथा इसके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष की तुलना में जांच अवधि में इसके उत्पादन में कमी आई है।

याचिकाकर्ता कंपनी का हिस्सा 47 % बनता है, अर्थात् जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादन के बड़े अनुपात को उपरोक्त नियम 2(ख) के अनुसार " घरेलू उद्योग " के रूप में माना गया है और इन जांच परिणामों के पूर्ववर्ती पैरा 13 में ऐसा ही उल्लेख किया गया है। इसलिए प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति, उत्पादन तथा क्षमता उपयोग में आई कमी के कारण हुई है। याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए घरेलू उद्योग की बिक्रियों

की मात्रा में भी पिछले वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान 26 % की कमी आई है । अनेक निर्यातकों तथा आयातकों ने यह तर्क दिया है कि बंद रहने की लंबी अवधि जो कि उद्योग के औसत से बहुत अधिक थी, के कारण उत्पादन में कमी आई थी तथा इस प्रकार क्षमता उपयोग का ह्रास हुआ । प्राधिकारी ने संयंत्र स्थल पर मौके पर की गई जांच के बाद इन तथ्यों की विस्तृत जांच की है तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ऐसा फिनाँल के भंडारण टैंकों के भीतर उत्पादन का भारी जमाव (जिसका संयोगवश दूसरे कन्टेनरों में भंडारण नहीं किया जा सकता था और जिसकी नए उत्पादन को शुरू करने से पहले खपत/बिक्री जरूरी थी) के कारण हुआ था जिसकी वजह से सामान्य रखरखाव के लिए कारखाने के बंद करने के अतिरिक्त उसे बार-बार बंद किया गया था । वस्तुतः प्राधिकारी यह मत अपनाने के लिए बाध्य हैं कि पाटन के कारण ही फिनाँल का कम उठाव हुआ है जिसके कारण भारी मात्रा में स्टॉक जमा हो गया और इस प्रकार कारखाने को बार-बार बंद किया गया ।

	एकक	1998-99	1999-00	2000-01	जांच अवधि	जांच अवधि वार्षिक
प्रभावी क्षमता	मी०टन	45000	45000	49000	49000	49000
उत्पादन	मी०टन	40142	39261	39055	29008	29008
क्षमता उपयोग	%	89.2	87.25	79.7	59.2	59.2
आरंभिक स्टॉक	मी०टन	2464	2885	1517	1920	2560
अंतिम स्टॉक	मी०टन	2885	1517	1920	2399	3199
स्वदेशी बिक्रियां	मी०टन	39956	40325	38633	28384	28384
उत्पादन	रु./मी०टन	100	103.69	133.47	135.82	135.82

विवरण						
बिक्री कीमत	रु./मी0टन	100	94	140	108.31	108.3
लाभ/हानि	रु./मी0टन	100	48	173	-25	-25
निवल ब्लॉक	रु. लाख	*****	*****	*****	*****	
सफल ब्लॉक	रु. लाख	*****	*****	*****	*****	

कीमत कटौती तथा कम कीमत पर बिक्री

34. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में पाटनरोधी नियमों के अनुबंध- II के नियम(iv)के अनुसार:

घरेलू उद्योग पाटित आयातों सके प्रभाव की जांच करते समय उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी आवश्यक आर्थिक कारकों तथा संकेतकों का मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, जिसमें बिक्रियों में प्राकृतिक एवं संभावित कमी, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश से आय या क्षमता का उपयोग ; घरेलू कीमतों पर प्रभाव डालने वाले कारकों, पाटन के मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह में वास्तविक एवं संभावित नकारात्मक प्रभावों, सूचियों, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि पूंजी निवेश बढ़ाने की क्षमता को शामिल करना चाहिए ।

कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय, इस बात की जांच करना आवश्यक समझा गया है कि क्या भारत में समान उत्पाद के मूल्य की तुलना में पाटित आयातों द्वारा मूल्यों में पर्याप्त मात्रा में मूल्यों को अन्यथा कम करना है । प्राधिकारी ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों के पहुंच मूल्य की तुलना निवल बिक्री प्राप्तियों से की है और पाया है कि पाटित आयातों द्वारा कीमतों में भारी कमी की गई है । आयातों के पहुंच मूल्य की घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्तियों से बहुत कम पाया गया है ।

प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के इस दावे की भी जांच की कि घरेलू उद्योग हानियों के कारण प्रभावित हो रहा है। प्राधिकारी नोट करते हैं क्षति का मूल्यांकन करने के लिए कम बिक्री कीमत एक महत्वपूर्ण संकेतक है। प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद की क्षतिरहित कीमत को निकाला है और कम बिक्री कीमत की सीमा पर पहुंचने के लिए इसकी तुलना पहुंच मूल्य से की है। यह विश्लेषण कम बिक्री कीमत के प्रभाव के महत्वपूर्ण स्तर को दर्शाता है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। इन आयातों का घरेलू बाजार में कीमतों पर महत्वपूर्ण कमी/ह्रास प्रभाव था, क्योंकि घरेलू उद्योग पाटित आयातों के मद्देनजर अपनी बिक्री कीमतें नहीं बढ़ा पा रहा था। इस प्रत्येक उपलब्ध साक्ष्यों की जांच दर्शाती है कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को अपनी बिक्रियों में समग्र रूप से क्षति हुई है।

बिक्री कीमत/लाभ प्रदत्ता

35. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतें उस कीमत से बहुत कम है जिससे घरेलू उद्योग को अपनी उत्पादन लागत की पर्याप्त प्राप्ति तथा तर्कसंगत आय का अर्जन होता। इस प्रकार पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को तर्कसंगत कीमत प्राप्त करने के लिए उपयुक्त कीमत वृद्धि करने से रोका है। उद्योग को कम बिक्री कीमत के कारण वास्तविक क्षति का सामना करना पड़ा है जिसके कारण उत्पादन की लागत की वसूली नहीं हुई जिसके बाद वित्तीय घाटे उठाने पड़ रहे हैं। प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन किए गए क्षति के अन्य मापदण्ड निम्नानुसार हैं:-

(क) घरेलू उद्योग के रोजगार स्तर में जांच अवधि के दौरान कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ख) जांच अवधि के दौरान अंतिम स्टॉकों में स्पष्ट वृद्धि जो यह संकेत करती है कि जांच अवधि के दौरान वस्तु सूची में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है।

(ग) कुछ निर्यातकों/उपयोक्ताओं की राय है कि जांच अवधि के दौरान एचसीएल को लाभ हुए हैं तथा एचओसीएल ने घाटा उठाया है। वे चाहते हैं प्राधिकारी इस मामले की जांच करें। प्राधिकारी ने एचसीएल द्वारा प्रस्तुत किए गए रिकार्डों की जांच की एवं इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस अभ्यावेदन में कोई सत्यता नहीं है कि एचसीएल ने जांच अवधि में लाभ कमाया। वास्तव में उन्होंने जांच अवधि के दौरान ***रु० का घाटा उठाया था।

(घ) क्षति साबित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण मापदण्ड कीमत में कमी तथा कम कीमत पर बिक्री है। प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह निर्धारित किया गया है कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

(ङ) इस प्रकार प्राधिकारी नोट करते हैं कि उद्योग को संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण क्षति हुई है। चूंकि संबद्ध वस्तु का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से बहुत कम है: उद्योग को अपनी कीमत उत्पादन लागत से बहुत कम रखने के लिए बाध्य होना पड़ा है।

माह/वर्ष	उत्पादन लागत रु० मी०टन	निवल बिक्री प्राप्ति रु० मी०टन	लाभ/हानि रु० मी० टन
98-99	100	100	100
99-00	103	94	48
2000-2001	133	140	173
अप्रैल 01-जून 01	135	132	115
जुलाई 01-सित० 01	132	107	-13.5
अक्टू० 01-दिस. -01	140	87	-170
जांच अवधि	135	108	-25

सूचीबद्ध आंकड़ों में 1998-99 को 100 माना गया है।

(च) उक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग जो वर्ष 98-99, 99-00 तथा 00-01 के दौरान लाभ कमा रहे थे ने जांच अवधि के दौरान बिक्री कीमत के घटने से घाटा उठाना शुरू कर दिया। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये पाटित कीमतों पर आयात के प्रत्यक्ष परिणामों के कारण हुआ है।

क्षति का संघयी मूल्यांकन

36. अनुबंध II (iii) के अनुसार, वे मामले जिनमें एक से अधिक देशों से किसी उत्पाद के आयात पर साथ-साथ पाटनरोधी जांच चल रही हो, प्राधिकारी के लिए ऐसे आयातों का संघयी

मूल्यांकन करना अपेक्षित है जबकि यह सुनिश्चित होता हो कि (क) प्रत्येक देश से आयात के संबंध में पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के रूप में व्यक्त 2% से अधिक हो तथा प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा समान वस्तु के आयातों का 3 % हो - और (ख) आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन आयातित वस्तु एवं समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए करना उपयुक्त है। प्राधिकारी ने पाया है कि प्रत्येक संबद्ध देश के संबंध में पाटन मार्जिन 2 % से अधिक है तथा प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा भी 3 % से अधिक है। प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु के आयातों का देश में उत्पादित समान वस्तु पर प्रभावों के संचयी मूल्यांकन को भी उपयुक्त समझा है और यह पाया है कि संबद्ध वस्तु के आयातों द्वारा घरेलू उद्योग पर क्षति का संचयी प्रभाव पड़ा है।

उक्त आर्थिक मापदण्ड संचयी एवं समग्र रूप से यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को पाटन के कारण वास्तविक क्षति हुई है।

ज. कारणात्मक संबंध

37. पाटनरोधी नियमों का अनुबंध-2 (V) बताता है कि यह प्रमाणित होना चाहिए कि पाटित आयात उक्त अनुबंध के पैरा 2 एवं 4 में उल्लिखित पाटन के प्रभावों के जरिए घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं। पाटित आयातों तथा घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का प्रमाणन निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों की जांच पर आधारित होना चाहिए। निर्दिष्ट प्राधिकारी को पाटित आयातों के अलावा किसी अन्य कारक की भी जांच करनी चाहिए जो उसी समय घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचा रहा हो, तथा इन कारकों द्वारा पहुंचाई गई क्षति को पाटित आयातों के साथ नहीं मिलाना चाहिए। जो कारक इस संबंध में संगत हो सकते हैं उनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं आयातों की मात्रा एवं कीमत जिन्हें पाटित कीमतों पर नहीं बेचा गया है, मांग में कमी या खपत के तरीकों में परिवर्तन व्यापार प्रतिबंधक कार्यकलाप एवं विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी विकास एवं निर्यात निष्पादन तथा घरेलू उद्योग की उत्पादकता।

याचिकाकर्ता के विचार

38. याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण उद्योग को क्षति हुई है। चूंकि संबद्ध वस्तु का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से बहुत कम है, उद्योग को अपनी कीमतों को उत्पादन की लागत से कम रखने के लिए बाध्य किया गया

है। इसलिए, उद्योग क्षतिरहित कीमत प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। पाटित आयातों के कारण कीमतों में कमी के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को भारी नुकसान हुआ है। उद्योग को अपनी बिक्रियां तथा उत्पादन बढ़ाने में भी बाधा पहुंची है। घरेलू उद्योग ने यह भी कहा है कि संबद्ध वस्तु की मांग में कोई नहीं कमी आई है और क्षति के लिए मांग में गिरावट को कारण नहीं माना जा सकता है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

39. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण क्षति हुई है, प्राधिकारी ने निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखा है:-

(क) प्राधिकारी यह पाते हैं कि संबद्ध वस्तु का ऐसा एक मात्र बाजार है जहां पाटित आयात घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं से सीधी प्रतिस्पर्धा करते हैं। मांग में कमी घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं है।

आयातित संबद्ध वस्तु तथा घरेलू उत्पादित वस्तुएं समान वस्तु हैं और उन्हें समान अनुप्रयोगों/अंतिम उपयोगों में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार आयातित स्रोत या घरेलू स्रोत से वस्तु की खरीद निर्धारण में कीमत सबसे महत्वपूर्ण कारक बन जाता है।

(ख) संबद्ध देशों से हुए आयात ने भारतीय बाजारों में कीमतों को इस हद तक कम किया है कि घरेलू उद्योग को भारत से संबद्ध वस्तु की बिक्री से अपने उत्पादन की पूरी लागत वसूल करने और तर्कसंगत लाभ कमाने में बाधा पहुंच रही थी।

(ग) जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित कीमतों पर बड़ी मात्रा में आयात के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को भारी नुकसान हुआ है।

झ. भारतीय उद्योग के हित

40. सामान्य तौर पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य ऐसे पाटन को समाप्त करना है जिससे भारतीय उद्योग को नुकसान हो रहा है तथा भारतीय बाजार में ऐसी खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की पुनःस्थिति लाना है, जो कि देश के सामान्य हित में है।

प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध वस्तुओं के उपयोग से विनिर्मित उत्पादों का कीमत स्तर प्रभावित होंगे और परिणामस्वरूप इन उत्पादों की सापेक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रभाव पड़ सकता है। किन्तु, पाटनरोधी उपायों से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटन द्वारा प्राप्त होने वाले अनुचित लाभ समाप्त होंगे, भारतीय उद्योग के ह्रास को रोका जाएगा और संबद्ध वस्तु के उपभोक्ताओं को व्यापक विकल्प उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपायों से संबद्ध देशों से आयात किसी भी प्रकार कम नहीं होंगे, इसलिए उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उपभोक्ता दो या इससे अधिक आपूर्ति के स्रोत रख सकेंगे।

अ. अन्य मुद्दे

रक्षोपाय का मुद्दा

41. कुछ हितबद्ध पक्षों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि चूंकि संबद्ध देशों की मूल की संबद्ध वस्तु पर रक्षोपाय शुल्क लागू कर दिया गया है, कोई पाटन रोधी शुल्क लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि रक्षोपाय शुल्क ने ही गंभीर क्षति जो कि वास्तविक क्षति का एक भाग है, के मुद्दे को इंगित कर दिया है जिसे पाटन रोधी शुल्क इंगित रकता है। इस संबंध में भी तर्क है कि रक्षोपाय शुल्क के रूप में क्षतिपूर्ति होने के पश्चात्, घरेलू उद्योग को पाटनरोधी शुल्क के रूप में दुगुना लाभ नहीं मिल सकता है।

प्राधिकारी ने इस मामले के संबंध में उन मुद्दों की जांच की है जहां रक्षोपाय शुल्क पाटनरोधी जांच शुरू होने से पहले लागू कर दिया गया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि

1. रक्षोपाय जांच की जांच अवधि वर्तमान जांच से अलग है और इस कारण क्षति निर्धारण को समान एवं सहसंबंधी नहीं माना जा सकता है।

इस तर्क के संबंध में कि महानिदेशक, रक्षोपाय ने गंभीर क्षति को समाप्त कर दिया है तथा इसी के लगा होने से वास्तविक क्षति भी समाप्त हो गई है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि निर्यातकों द्वारा अब उचित कीमत (रक्षोपाय शुल्क) की स्थिति से अनुचित कीमत का सहारा लेने से क्षति की प्रकृति में वास्तविक परिवर्तन हुआ है। प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि याचिकाकर्ता को अब पाटन रोधी संरक्षण की आवश्यकता है क्योंकि निर्यातकों ने अपने उत्पादों को अनुचित कीमत पर नियत किया है। इस प्रकार निर्यातकों/उपभोक्ताओं द्वारा उठाये गए इस तर्क में कोई सत्यता

नहीं है कि याचिकाकर्ता को दोहरा संरक्षण मिल रहा है। निर्यातकों एवं आयातकों/उपयोक्ताओं द्वारा यह दावा किया गया है कि पाटनरोधी शुल्क लगा करने से घरेलू उद्योग को दुगुना संरक्षण मिलने की संभावना है। दूसरी ओर घरेलू उद्योग ने कहा है कि यह अनुरोध किया है कि संबद्ध वस्तु के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क इसलिए लगाया गया है ताकि अनुचित आयातों जिनके लिए पाटनरोधी शुल्क अपेक्षित होता है की तुलना में उचित आयातों के कारण हुई क्षति (गंभीर क्षति) पर विचार किया जा सकता है। प्राधिकारी ने इस संबंध में मुद्दों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है और यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी जांच का उद्देश्य यह जांच करना है कि क्या जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से अनुचित आयातों के कारण फर्म को क्षति हो रही है। प्राधिकारी महसूस करते हैं कि क्षति का होना पाटनरोधी एवं रक्षोपाय जांच के लिए सामान्य बात है तथा पाटनरोधी एवं रक्षोपाय शुल्क लागू करने का उद्देश्य घरेलू उद्योग को सीमित समयावधि के लिए क्रमशः पाटित/ अनुचित एवं उचित आयातों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करना है। प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि क्षति मार्जिन की गणना के समय, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु की पहुंच मूल्य निर्धारण में रक्षोपाय शुल्क को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

एकाधिकार संबंधी मुद्दा

42. कुछ हितबद्ध पक्षों द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि एचओसीएल देश में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है क्योंकि हरदीलिया जिसको सेनेकटेडी द्वारा अपने अधिपत्य में ले लिया गया है और इसलिए उनके द्वारा वर्तमान याचिका किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए दायर की गई है। इसके अलावा याचिकाकर्ता की कुल क्षमता देश में फेनोल की मांग से कम है तथा संयंत्र का आकार इस देश की कुल मांग को पूरा करने की दृष्टि से बहुत छोटा है। यह भी तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रयोग की जा रही प्रौद्योगिकी अप्रचलित है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु की खराब गुणवत्ता तथा फेनोल की स्थायी उत्पादन लगातार, अवमूल्यन एवं शीर्षों के विभाजन के लिए अपनाये गये तरीकों से संबंधित मुद्दे भी उठाये गये हैं। यह भी कहा गया है कि भारत को किए जा रहे निर्यात अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रचलित कीमतों पर किए जा रहे हैं।

(iii) प्राधिकारी ने उपरोक्त मुद्दों की जांच की है। पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि घरेलू उद्योग को पाटन के कारण हुई क्षति का पर्याप्त रूप से निर्धारण हो सके। यह तथ्य कि देश में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक (हर दीलिया जिसे सेनेकटेडी द्वारा हाथ में ले

लिया गया है, को छोड़कर) है, घरेलू उत्पादकों के इस अधिकार को किसी भी तरह से बाधित नहीं करता है कि वे निर्दिष्ट प्राधिकारी से पाटनरोधी नियमों के अंतर्गत पाटित आयातों के विरुद्ध राहत की मांग करे। यह एक स्वीकृत विचार है कि पाटनरोधी शुल्क प्रकृति एवं रूप में पाटन के विकृत व्यापार व्यवहार के विरुद्ध उपचार प्रदान करता है। इसके अलावा, पाटनरोधी शुल्क किन्हीं स्रोतों से आयातों को प्रतिबंधित अथवा रोकने का प्रस्ताव नहीं करता है और इसलिए घरेलू आपूर्ति के देश में कुल मांग से कम होने का मुद्दा संगत नहीं है। चूंकि भारतीय औद्योगिक उपयोक्ताओं को आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध है, याचिकाकर्ता कंपनी की उपभोक्ताओं का शोषण करने की एकाधिकारी स्थिति संबंधी कार्यकलापों की आशंका गलत साबित होती है।

डीजीसीआईएंडएस तथा द्वितीयक स्रोतों से आंकड़े संबंधी मुद्दे

43. निर्यातकों तथा भारत में उपयोक्ता उद्योगों की एसोसिएशनों द्वारा यह दावा किया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा जमा कराये गये आंकड़े क्षति निर्धारण के लिए स्वीकार्य नहीं होने चाहिए क्योंकि ये आंकड़े द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त किए गए हैं और प्राधिकारी को पाटनरोधी जांच के लिए केवल प्राथमिक स्रोतों (डीजीसीआईएंडएस) से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग करना चाहिए। प्राधिकारी ने इस मामले की जांच की है और नोट किया है कि संबद्ध वस्तु के आयात संबंधी डीजीसीआईएंडएस आंकड़े निर्यातकों तथा घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से बहुत अधिक भिन्न हैं। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु के बहुत से कार्गो कांडला पत्तन पर आ चुके थे। प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता तथा निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की कांडला पत्तन सीमाशुल्क द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से प्रति जांच की है और प्रति जांच के पश्चात प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि डीजीसीआईएंडएस के आंकड़े अधिकांशतः अपूर्ण हैं और जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से हुए सभी सौदों के बारे में जानकारी नहीं देते हैं। इसलिए प्राधिकारी ने दक्षिण अफ्रीका से बल्क आयातों तथा यूरोपीय संघ से संबद्ध वस्तु के आयातों के लिए कांडला सीमाशुल्क द्वारा प्रस्तुत पत्तन आंकड़ों को स्वीकार किया।

दक्षिण अफ्रीका से ड्रम आयातों के लिए प्राधिकारी ने निर्यातकों के अनुरोध को उपयुक्त माना है। सिंगापुर से आयातों के संबंध में, प्राधिकारी ने सिंगापुर से भारत में संबद्ध वस्तु के आयातों के लिए सिंगापुर ट्रेड आंकड़े लिए हैं तथा सिंगापुर से आयातों के संबंध में निर्यातकों के अनुरोध को उचित समझा है।

निष्कर्ष

44. पूर्वोक्त पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि:

(i) संबद्ध देशों से भारत को फेनोल या विचाराधीन उत्पाद का निर्यात इसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है ;

(ii) भारतीय उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है ;

(iii) यह क्षति संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण हुई है ।

(iv) प्राधिकारी घरेलू उद्योग की क्षति को समाप्त करने के उद्देश्य से, अंतिम रूप से निर्धारण होने तक, संबद्ध देशों से फेनोल के सभी आयातों पर अनन्तिम पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक समझते हैं । प्राधिकारी द्वारा ज्ञात निर्यातकों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन उपरोक्त पैराग्राफों में दर्शाया गया है । प्राधिकारी पाटन मार्जिन के बराबर अथवा उससे कम पाटनरोधी शुल्क की राशि को सिफारिश करने का प्रस्ताव करते हैं जिसे यदि वसूल किया जाएगा तो उससे घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त हो जाएगी । क्षति का निर्धारण करने के उद्देश्य से, आयातों के पहुंच मूल्य की तुलना जांच अवधि के लिए निर्धारित याचिकाकर्ता कंपनियों की क्षति रहित बिक्री कीमत के साथ करने का प्रस्ताव है ।

(v) तदनुसार, प्राधिकारी यह सिफारिश करते हैं कि अंतिम निर्धारण होने तक संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के सभी आयातों पर केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से अनन्तिम पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए । सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सीमाशुल्क टैरिफ के अध्याय 29 और 27 के अंतर्गत आने वाले फेनोल के सभी आयातों पर पाटनरोधी शुल्क नीचे तालिका में दी गई धनराशि होगी जिसे केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से लगाया जाएगा ।

क्र०सं०	देश/निर्यातक	शुल्क की राशि अमरीकी डालर प्र० मी. टन
1.	सिंगापुर: क. मित्सुई एंड कं० लि० ख. मित्सुई फेनोल सिंगापुर पीटीई लि० ग. अन्य निर्यातक	95.77 101.62 161.38
2.	दक्षिण अफ्रीका:	

	क. मेरोसोल 1. बल्क बिक्रियां 2. ड्रम बिक्रियां ख. अन्य निर्यातक 1. बल्क बिक्रियां 2. ड्रम बिक्रियां	89.12 24.76 222.74 130.60
3.	यूरोपीय संघ	109.49

(vi) इस उद्देश्य के लिए आयातों का पहुंच मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 3, 3क, 9 और 9क के तहत लगाए गए अतिरिक्त सीमाशुल्क को छोड़कर, सभी प्रकार के शुल्कों सहित सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के अधीन सीमाशुल्क द्वारा यथा आकलन योग्य मूल्य होगा ।

ट. आगे की प्रक्रिया:

45. प्रारंभिक निष्कर्षों को अधिसूचित करने के बाद निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:

(क) प्राधिकारी सभी हितबद्ध पार्टियों से इन निष्कर्षों के बारे में टिप्पणियां अमंत्रित करेंगे और उन पर अंतिम निष्कर्षों में विचार किया जाएगा ;

(ख) प्राधिकारी द्वारा निर्यातकों, आयातकों, याचिकाकर्ताओं तथा अन्य ज्ञात हितबद्ध पार्टियों को अलग से लिखा जा रहा है, जो प्रारंभिक परिणामों की तारीख से 40 दिनों के अन्दर अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं । कोई अन्य हितबद्ध पार्टी भी इन निष्कर्षों के प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों के भीतर अपने विचारों से अवगत करा सकती है ;

(ग) प्राधिकारी सभी हितबद्ध पार्टियों को मौखिक अनुरोध करने का अवसर प्रदान करेंगे जिन्हें उसके बाद लिखित में प्रस्तुत करना होगा ।

(घ) प्राधिकारी आवश्यक सीमा तक और आगे जांच करेंगे ।

(ड.) प्राधिकारी द्वारा अंतिम निष्कर्षों को घोषणा करने से पूर्व आवश्यक तथ्यों का खुलासा किया जाएगा ।

एल. बी. सप्तश्रृषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties)****PRELIMINARY FINDINGS**

New Delhi, the 24th June, 2002

Subject : Anti-dumping investigation concerning imports of Phenol from the European Union, Singapore and South Africa—Preliminary findings.

No. 14/4/2002-DGAD.— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof;

A. PROCEDURE

2. The procedure described below has been followed:

- (i) The Designated Authority (hereinafter referred to as Authority), under the above Rules, received a written petition from M/s Hindustan Organic Chemicals Limited (HOCL) on behalf of the domestic industry, alleging dumping of Phenol (hereinafter referred to as subject goods) originating in and exported from European Union, Singapore and South Africa (hereinafter referred to as subject countries);
- (ii) The Authority notified the Embassies/Representative of the subject countries in India about the receipt of dumping application made by the petitioner before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 supra;
- (iii) The Authority issued a Public Notice dated 15th February 2002 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti dumping proceedings concerning imports of Phenol originating in or exported from the subject countries falling under Customs Sub-heading 2907.11 and 2707.60 under chapter 29 and 27 respectively of the Customs Tariff Act, 1975;
- (iv) The Authority forwarded copy of the said public notice to the known exporters, importers, users, industry associations and to the

complainants and gave them an opportunity to make their views known in writing;

- (v) According to sub-rule (3) of Rule 6 supra, the Authority provided a copy of the petition to all the known exporters; and Embassies/representatives of subject countries in India.
- (vi) The Authority sent questionnaires, to elicit relevant information, to the following exporters from the subject countries:
 - a. Phenolchemie GmbH, Postfach 508, Germany.
 - b. Enichem, Piazza Boldrini 1, Italy.
 - c. Mitsui & Co Ltd, 16 Raffles Quay, Singapore.
 - d. Merisol, Sasolberg, South Africa
- (vii) The Embassies/representative of subject countries in New Delhi were also informed about the initiation of investigation and were requested to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time;
- (viii) The questionnaire was sent to the following users/importers of subject goods:

(A) Segment wise list of major consumers:

PF Resins

- a) PF Moulding Powder: XPRO India, Division Cimmco Birla Ltd, Kandivali West, Mumbai 400067.
- b) Laminates: Bakelite Hylam Ltd, Sanathanagar, Hyderabad, AP
- c) Plywood/Particle Boards: Greenply Industries Ltd, Ratnagiri, Maharashtra.
- d) Foundries/Abrasives: Gargi Huttenes Albertus Pvt Ltd, 205 Vasant Vihar Complex, Chembur, Mumbai 400074

Drugs and Pharmaceuticals

Alta Laboratories Ltd, Alta Bhavan, Senapati Bapat marg, Dadar, Mumbai 400028.

Pesticides and Insecticides:

United Phosphorus Ltd, Readymoney Terrace, Dr. Annie Besant Rd. Mumbai

Syntans

Colour Chem Ltd, Mumbai Agra road, Balkum, Thane, Mumbai.

Alkyl Phenols and Diphenyl Oxide

Herdillia Chemicals Ltd, 13th Floor, Air India Building, Nariman Point, Mumbai

(B) Addresses of Indian importers (Traders)

C. J. Shah and Company
105, Bajaj Bhawan
10th Floor, Nariman Point
Mumbai – 400021

Haresh Kumar and Company
1212, Maker Chambers 5
Jamnalal Bajaj Road,
Nariman Point
Mumbai – 400021

PCL Industries
M – 105, Connaught Place
New Delhi – 110001

Kantilal Manilal and Company
16, Princess Street
Mumbai – 400003

Sonkamal Enterprises
10, Dev Darshan Apartment
Old Nagardas Road
Andheri (East)
Mumbai-400 069

Khetan Brothers
C-17, Dalia Industrial Area
Off New Link Road
Opposite Laxmi Industrial Estate
Andheri (West)
Mumbai-400 058

Shubham Dyes & Chemicals Limited
1 / 26, Roop Nagar
Delhi-110 007

(C) Domestic Associations of User Industries

- a. Indian associations of user industries:
16, Mumbai Samachar Marg, Mumbai 400023
- b. Society of thermosetting Industries:
TIPCO, Rani sati marg, Malad(East), Mumbai 400097
- c. Indian Laminates Mfrs Associations
Das chambers, Mumbai 400023

- (ix) Mitsui Phenol Singapore Pte, Singapore had asked for some more time to respond in view of the delay in receiving the letter. M/s Kesar Petro Products, a user of the subject goods had also asked for extension of time for filing their reply as their name was not there in the petition submitted by the domestic industry. One-week extension was allowed to both the exporter as well as the user.
- (x) The Authority kept available non-confidential version of the evidence resented by various interested parties in the form of a public file maintained by the Authority and kept open for inspection by the interested parties;
- (xi) ***** In this notification represents information furnished by the interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- (xii) The investigation covered the period from 1st April 2001 to 31st Dec 2001.
- (xiii) Additional details regarding injury were sought from the petitioner, which were also furnished.
- (xiv) The Authority conducted on-the-spot verification of the domestic industry to the extent considered necessary.
- (xv) The cost of production of the domestic industry was also analyzed to work out optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) based on the information furnished by petitioner so as to ascertain if anti dumping duty lower than dumping margin would be sufficient to remove injury to domestic industry.
- (xvi) Copies of initiation notice were also sent to FICCI, CII, ASSOCHAM etc., for wider circulation.

B. PETITIONER'S VIEWS

3. The petitioners have made the following major points in to their submissions:

- i. The product under consideration in the present petition is Phenol also known as carbolic acid. It is produced by the oxidation of Cumene using air at elevated temperature and pressures. The product is then alkali washed and concentrated to a higher strength and then mixed with

- H₂SO₄, which causes a cleavage reaction to give Phenol and Acetone. This is then washed to remove acidity and distilled in a series of distillation columns to give Phenol and Acetone.
- ii. It is classified under chapter 29 of Customs tariff Act under Customs sub heading 2907.11. However it is also imported under Chapter 27 under subheading 2707.60.
 - iii. There are three producers of Phenol in India, who have created capacity to produce Phenol. Apart from the petitioner, M/s. Herdillia Chemicals Limited and M/s. Neyveli Lignite Corporation have also created capacity to produce Phenol. However, The petitioner has submitted that M/s. Neyveli Lignites is relatively much small producer of Phenol.
 - iv. There is no difference in Phenol produced by the Indian industry and Phenol exported from the subject countries. Phenol produced by the Indian industry and imported from the subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology (followed by most of the producers from the subject countries), functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. Phenol produced by the petitioner and imported from the subject countries should be treated as like articles in accordance with the anti-dumping Rules
 - v. As regards the normal value in the case of subject countries, the petitioner has not been able to get evidence either with regards to the prices of phenol in subject countries or price lists of the exporters. They have also not been able to get any evidence of exports from subject countries to other countries (Except for Singapore). Only in the case of Singapore they have been able to get evidence of price at which the producer in Singapore has exported phenol to various countries. The petitioner believes that there is a significant difference in the price at which the material has been exported to India and the price at which the Singapore exporter exported the material to other countries. In fact the prices at which Singapore exporter has been exporting the product to India has been benchmarking the price of Phenol in India and is forcing other producers in other countries to reduce the prices and resort to dumping. The petitioner has been able to get the information about exports of Phenol from Singapore to India and top ten countries. Normal value has been determined on the basis of exports from Singapore to Malaysia and Thailand. As regards EU and South Africa the petitioner has claimed normal value on the constructed cost of production after taking the price at which the basic raw material has been imported into India.
 - vi. The petitioner has claimed export price on the basis of published data of DGCI&S, Kolkata. However the above information has been relied upon for determination of value and volume of imports of phenol in India for

the period up to June 20001. For the later period of the POI (from July onwards), the petitioner has procured information from secondary sources (From Kandla port) as they maintain that DGCI&S data is incomplete and does not reflect the total imports. In the case of Singapore the petitioner has given an evidence of the subject goods exported from Singapore to India as per Singapore Trade Statistics.

- vii. The petitioner has submitted that dumping margin from all subject countries is not only more than de-minimus but also substantial. In fact cumulative assessment of the effects of imports is appropriate since the exports from the subject countries directly compete with the prices offered by the domestic industry in the India market. The authority is therefore requested to assess injury to the domestic industry cumulatively from the subject countries.
- viii. Import statistics show that the quantum of imports from subject countries has increased in a significant way. Volume of imports has increased in spite of imposition of safeguard duty.
- ix. Various economic parameters suggest that the petitioner has suffered injury due to import from subject country. Production and capacity utilization has very significantly declined in the current year. The domestic industry has been forced to restrict its production due to dumping from subject countries.
- x. Prices of imported Phenol fell sharply causing severe price depression. The prices of imported Phenol when adjusted for price increases actually fell even below the already low levels of the year 1989-99 which covered the first period of the safeguard investigations.
- xi. The petitioner has added that the price (after including the basic custom duty) at which the material is imported is not only below the selling price of the domestic industry but also are not permitting recovery of the full cost of production to the petitioner. Thus the imports are causing severe price undercutting, depression, and suppression in the market.
- xii. Thus selling prices of the domestic industry were far below the costs of production, resulting in the severe financial losses to the domestic industry.
- xiii. Thus various economic parameters relating to the domestic industry collectively and cumulatively establish that the domestic industry has suffered injury despite safeguard duty in place and the injury is directly caused by dumped imports from subject countries.

C. EXPORTERS', IMPORTERS', USERS' AND OTHER INTERESTED PARTIES' VIEWS:

4. Responses have been received from the following exporters and exporters Organizations.

- i. Mitsui & Co., Ltd Singapore Branch, Singapore.
- ii. Mitsui Phenol Singapore Pte Ltd., Singapore.

iii. Merisol RSA (Pty) Ltd., Johannesburg, South Africa

5. The submissions made and/or the information provided by the above as follows:

(i) Mitsui & Co., Ltd Singapore Branch, Singapore

- a. M/s Mitsui & Co. Ltd. has held that they do not dump any exports into India and cause any damage to Indian local producers.
- b. The price of exports to India has been set in accordance with world's supply/demand balance as well as in consideration of the international prices and competition with other suppliers.
- c. Demand for phenol in 2001 fell sharply all over the world due to severely depressed economic situation. Total demand for phenol in 2001 was approximately at 6.5 million tones, which was 3% less than compared with the previous year. However, the total phenol production capacity reached around 8 million tones, which means that average plant utilisation ration was deemed at about 82-83% throughout year 2001, which was extremely low in view of last five years. For example, the standard market prices in Asia were about US \$ 600/MT CIF at the beginning of 2001 and fell to US\$400/MT CIF by the end of 2001.
- d. Indian demand of phenol has been growing with a steady growth in Indian economy and accordingly demand for imported phenol has increased remarkably. While total demand is estimated at around 110-120 Kilo tones per year, production of all domestic producers is only about 60 kilo tones per year which means India needs a constant import of 50-60 kilo tones per year.
- e. Mitsui Phenol Singapore Ltd (MPHS) is one of the newest and biggest plants in the world and is most competitive in terms of stable production, high productivity and low production cost. As a result of imports from Singapore many customers could improve their profitability, which should have contributed a lot to the Indian economy while domestic producers often have production problems and unstable supply. In fact it was not import of Singaporean product, but rather domestic producer's uncompetitive nature and delays in their restructuring of their production and supply system that brought heavy injury to domestic industry.
- f. The exporter has added that phenol's price dropped very sharply due to a sudden occurrence of excessive demand and supply imbalance and a large decrease in the raw material price. The price drop happened not only in India but also throughout the world.
- g. Phenol itself is not different in terms of chemicals characteristic. However, overall services and quality controls, as well as the value added at the factory for the end customers, are different.

- h. HOCL plant is too old and the yield ratio is too poor to cover their costs. On the other hand, MBHS has the latest advanced technology.
- i. There is a large phenol consumer in Singapore and the price of this consumer should be taken as a normal value.
- j. As regards substantial increase in imports from the subject countries in absolute terms, the exporter has held that demand in India has increased a lot while new capacity was built in Singapore. In addition, world demand outside India slowed considerably after the year 2001. Imports increased due to growing Indian economy and not due to dumping price. The fact that HOC sales decreased less than 30 Kilo tones is due to their technical and financial problems.

Mitsui Phenol Singapore Pte Ltd (MPSL), Singapore Branch:

- a. Mitsui Phenol Singapore Pte Ltd is owned by M/s Mitsui Chemicals Inc. Japan and Mitsui & Co, Japan.
- b. The petitioner has submitted similar arguments to the one submitted by Exporter M/s Mitsui & Co Ltd as mentioned in earlier paragraph. These are not being repeated for the sake of brevity. However their normal value and export price are being dealt separately as per their submission in the relevant headings.

M/s Merisol RSA (Pty)., South Africa.

- a. M/s Merisol RSA (pty) has responded to the questionnaire and has given arguments in their submissions.
- b. **STANDING:** The petitioners themselves admit that during the period of investigation they accounted for less than 50 of the domestic production. According to rule 5(3) in order to constitute a valid application, the following two conditions have to be satisfied:
 - i) Their domestic producers expressly supporting the application must account for not less than 25% of the total production of like articles by the domestic industry in India; and
 - ii) The domestic producers expressly supporting the application must account for more than 50% of total production of the like articles by those expressly supporting and those opposing the application. While the petitioners may satisfy part a) of the test, the onus is on the designated authority to verify part b) of the test and until such time as is done, it is submitted that this initiation is ultra vires.
 - iii) **HERDILLIA DATA NOT AVAILBALE:** It is pointed that M/s Herdillia was taken over by Schenectady Group on 1st July 2001. M/s

Merisol RSA (pty) holds that M/s Herdillia has suffered no injury during the period of investigation and this fact must be checked while determining the injury if any to the domestic industry in India otherwise M/s Herdillia Chemicals Ltd would enjoy the benefits of anti-dumping duty without disclosing any injury at all.

iv) DETERMINATION OF INJURY MARGIN: The petitioner has claimed a landed value without considering the existing safeguard duty on the product. In order to determine the injury margin, if any, to the domestic industry, the safeguard must be considered in calculating landed value as doing otherwise would be tantamount to doubly protecting the domestic industry, first for their own inefficiency and second for the injury caused by the alleged dumping. Both of these manifests in injury margin to the petitioners.

v) SAFEGUARDS DUTIES AND INJURY: As this is first case in India where antidumping duties have been petitioned for during the pendency of the safeguard duty, the Hon'ble designated authority must isolate the injury caused by the inefficiencies of the domestic industry themselves.

IMPORTERS AND USERS

6. The Following importers and users have responded to the questionnaire:

a. All India Association of Industries: Names of the industries who have made their submissions through this representation are:

- i. Resins and Plastics Ltd.
- ii. Neeluxe India Limited
- iii. United Phosphorus Ltd.
- iv. Alka Laboratories Ltd.
- v. Dujoowala Resins & Terpenes Ltd.
- vi. IVP Ltd.
- vii. Dujodwala Paper Chemicals Ltd.
- viii. Gargi Huttenes Albertus Ltd.
- ix. Dujodwala Products Ltd.
- x. Marvel Themosets Pvt. Ltd.
- xi. XPRO India Ltd.
- xii. BASF India Ltd.
- xiii. United Metachem Pvt. Ltd.
- xiv. Colour Chem Ltd.

b. M/s Kesar Petroproducts Ltd.

c. Associations of users and consumers of Phenol

7. Major points/arguments as submitted by the various industry associations and Users organizations as mentioned above are as follows:

- a. Anti-dumping applications are filed by or on behalf of the domestic industry in terms of the provisions of the Customs Tariff (Identification, Assessment And Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995. The relevant section is Rule 5 of Anti-Dumping act, which is reproduced below:

“5. Initiation of investigation. –

(1) Except as provided in sub-rule (4), the designated authority shall initiate an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping only upon receipt of a written application by or on behalf of the domestic industry.

(2) An application under sub-rule (1) shall be in the form as maybe specified by the designated authority and the application shall be supported by evidence of –

- (a) Dumping
- (b) Injury, where applicable, and
- (c) Where applicable, a causal link between such dumped imports and alleged injury.

(3) The designated authority shall not initiate an investigation pursuant to an application made under sub-rule (1) unless -

(a) It determines, on the basis of an examination of the degree of support for, or opposition to the application expressed by domestic producers of the like product, that the application has been made by or on behalf of the domestic industry:

Provided that no investigation shall be initiated if domestic producers expressly supporting the application account for less than twenty five per cent of the total production of the like article by the domestic industry, and

(b) it examines the accuracy and adequacy of the evidence provided in the application and satisfies itself that there is sufficient evidence regarding –

- (i) Dumping,
- (ii) Injury, where applicable; and

(iii) Where applicable, a casual link between such dumped imports and the alleged injury, to justify the initiation of an investigation.

Explanation. - For the purpose of this rule the application shall be deemed to have been made by or on behalf of the domestic industry, if it is supported by those domestic producers whose collective output constitute more than fifty per cent of the total production of the like article produced by that portion of the domestic industry expressing either support for or opposition, as the case may be, to the application.

Under the provisions of the Anti-dumping Rules, a petition is required to be supported by those units, which account for at least 25% of the production of the entire domestic industry. The explanation to the Rule further prescribes that the application should have the support of at least 50% of those producers who express support or opposition to the application. In other words, there are two tests to be passed for an application to be considered as a valid application under the provisions of Rule 5 of the Anti-dumping Rules, i.e., 25% of the total production and 50% of those who are either supporting or opposing the application. It is obligatory on the Designated Authority to ensure that both the tests are fulfilled before initiation of the case.

In the instant case, the petitioner namely HOCL admittedly accounts for 46.11% of the total production of the domestic industry. The Designated Authority has not made any effort to find out whether there is any opposition to the application or not. In this connection, it is important to see Rule 5(3)(b) which clearly obligates the Designated Authority to determine the standing prior to the initiation only. In fact this aspect of the proceedings is required to be 'determined' prior to the investigation itself. As the Designated Authority has failed to carry out the mandatory tests, and being a failure to satisfy a condition precedent, the initiation of the investigation cannot survive

- b. It is pertinent to note that in the final findings of the DG Safeguard dated 14/5/99 on the original application of HOCL and Herdillia Chemicals Ltd, it has been concluded by DG safeguard that there is no proof of dumping of phenol in India and hence the case was considered fit to be examined by DG safeguard for safeguard duty.
- c. It is seen that in the present petition HOCL has taken exactly the opposite stand and claimed that phenol is being dumped in India on the basis of certain figures published in Singapore Trade Statistics. Even now HOC has not been able to produce any data on the selling prices of phenol in the domestic markets of the exporting countries. Moreover, after getting the benefit of Safeguard Duty on the basis that it is not a case of dumping, HOC is now trying to get double benefit by applying for anti-dumping duty on phenol.

- d. HOC has claimed that the dumping of Phenol started from April'01. It has also admitted there was no safeguard duty (SGD) in force in the period April-Déc'01 in so far as Singapore and South Africa are concerned. In this connection it is to be mentioned that representation was already made on this subject by Phenol manufacturers to DG (Safeguard) on the grounds of spurt of imports from South Africa & Singapore from April'01 and more particularly major increase in imports in July'01. On the basis of this representation DG (Safeguard) has already recommended levy of SGD on imports from Malaysia, South Africa and Singapore in his final findings on 11th Dec'01. Thus the relief sought by Phenol manufacturers for increase in imports from Singapore and South Africa has already been recommended by DG (Safeguard) and there is no case for granting further relief on the same grounds by levy of Anti Dumping Duty.
- e. Initiation of Anti-dumping Investigation is Improper: DG (Safeguards) had initiated investigations for imposition of safeguard duty against Malaysia, Singapore as well as South Africa taking into account the period of investigation from April 2001 onwards. Based on a thorough examination, DG (Safeguards) recommended safeguard duties on imports from these sources also.
- f. As against the concept of 'serious injury' to the domestic industry under the safeguard provisions, the Anti-dumping Rules provide only for 'material injury'. Thus if sufficient duties have been recommended for removing 'serious injury', it is inconceivable that an additional amount is required for removing 'material injury' which under the very same Act is a less serious situation. Thus, it is obvious that an anti-dumping investigation cannot be initiated in a case where safeguard duties have been recommended taking into account almost the same period of investigation.

It is stated by the petitioner that dumping of Phenol started since July 2001. It is further seen that HOCL has submitted import statistic only up to Nov'01 and no statistic is submitted for the month of Dec'01. It is submitted that this period of 5 months is too short a period for taking the decision on major issue like levy of Anti Dumping duty which has got long term impact on the users of phenol in the country.

- h. Users maintain that low stock created uncertainty about the availability of phenol, which prompted phenol users to plan their requirement for a couple of months. The stock of Acetone, a co-product of phenol had also come down and the suppliers of Acetone in the international market link it with supply of phenol. Thus shortage of phenol and acetone was the main reason for imports in July-Nov'01.

- h. It is to be noted that in July'01 a major additional capacity of 2,00,000 MT set up by Mitsui Corporation in Singapore was commissioned. This additional capacity was one of the main grounds for which SGD was extended for two years.
- i. Apart from shortfall in production, HOC pricing policy has also to be blamed for imports during this period as consistent rise in prices along with lack of sufficient stock resulted in the consumers planning for imports, which are required to be arranged in bulk.
- j. During the period April-December, 01 HOC plant was shut down for 68 days for different reasons, which also can be the ground of low production of Phenol.
- k. Users also maintain that there is an added cost to imports as product is to be stored in special road tankers with insulation and steam coils, which add to about 15% extra cost to the landed cost of imports. Domestic manufacturers are thus gaining around 15% price advantage as compared to imports.
- l. Monopolistic Market Control of HOC on Phenol Market: Subsequent to the extension of SGD period by 2 years from 30.06.01 onwards there was a major development in form of acquisition of HCL by Schenectady of USA, which is a major consumer of Phenol in India and the world. This has resulted in HCL Phenol capacity becoming captive to Schenectady and HOC remaining the only merchant manufacturer of Phenol in India. This monopolistic position of HOC is a factor, which has to be taken into account while considering grant of any further duty protection to Phenol.
- m. HOC is not in a position to manufacture phenol of the grade required for manufacture of BPA, which goes into the manufacture of polycarbonates. HOC has admitted its inability to produce this grade of phenol and hence this grade should be exempted from any duty protection except the basic custom duty. BPA manufacturer has to incur additional cost of Rs.3000 per MT for using HOC phenol instead of PC grade phenol.
- n. Normal value: The petitioner has not given any information regarding the price of this product in the domestic market of the exporting countries or price lists of the exporter of these countries. They have not been able to get any accurate & adequate evidence of the exports from the subject countries to other countries (except for Singapore). Additionally no information is given in respect of the cost of production of the subject goods in the country of origin along with permissible additions. Instead of this, the petitioner has worked out "constructed cost of production" of phenol in the exporting countries and requested the "Designated Authority" to accept the same. It is submitted that Normal Value based on such constructed cost of production may not be accepted as technological development is much superior in these countries and hence their consumption norms of raw materials and particularly utilities like steam, chilled water, cooling water,

compressed air etc., are much tighter than the plants operated in India. Their manpower requirement is very less as compared to India and rate of interest prevailing in these countries are also much below than India. Thus, the Users maintain that it would not be correct to construct the cost of production on the basis of Indian Standards for deciding such important issues. It is also pointed out that in case of South Africa the Petitioner is not even aware of the manufacturing process and hence his ability to work out the constructed cost of production is highly questionable. As regards export price, Petitioners has submitted data pertaining to exports from Singapore to India and other countries. This information is based on a trade statistics published by statlink, which does not appear to be official publication of Singapore Trade Authority.

- o. The petitioner has again mentioned about the difference between the statistics of import reported by DGCI&S and DG Safeguard but as pointed out by us earlier, the figures of DG Safeguard were based on market information given by the phenol manufacturers whereas information published by DGCI&S is the correct information on imports.
- p. One of the major parameters of injury cited by the petitioners is the decline in the profitability of HOCL during POI. As per table shown in page 17 of the petition, there was a profit for the quarter April 01-June01 as well as in the earlier 3 years from 98-99 to 00-01 but in the quarters July01-sep01 and Oct 01- Dec01 there is a loss. In fact a reading of the profit figures of HOC from the year 1988-89 to 2000-01 show that the profit of Kochi unit has gone up very high from 14% to 990% over the period of 10 years up to 1997-98. There after Kochi unit is still making high profit continuously and in the year 2000-01 profits was Rs. *****lacs.

Year	Rs crores		
	Rasayani	Kochi	Total
98-99	-41.24	10.17	-23.07
99-00	-109.92	4.90	-105.02
2000-01	-80.43	41.37	-39.05

- q. It is however seen that HOCL's quarterly forecast of profit based on unaudited results are not proved to be correct at the end of the financial year. It is thus not advisable to accept the figures of HOC of the loss suffered by it up to Dec'01 unless its audited financial results are available.
- r. It is to be noted that HOCL's phenol plant is more than 12 years old and thus it is fully depreciated and is free from term loan liabilities. It

however appears that depreciation and interest are still added as cost components.

- s. Petitioners understanding that the cost of the production from coal tar route is higher than the route followed by HOCL is without any proof and must not be accepted. Hence constructed cost of production as worked out by petitioner must not be considered on the same ground. As per our information the cost of production of phenol from coal tar based process is definitely lower due to lower cost of raw materials as compared to benzene and propylene, which are expensive petroleum based raw materials.
- t. The export prices from subject countries were always in the range of RS. 18000 TPA Rs. 21000 except in 2000-01 when the prices went up mainly due to high cost of raw materials due to very high crude prices. Now that the crude price have come down the prices of phenol have again returned to their normal value. . Thus the price at which phenol was imported into India from Singapore in the period under investigation is in keeping with this trend.
- u. The rated capacity of HOC's phenol plant is 40,000 TPA. It is seen that HOCL was achieving almost full capacity utilisation in the last 3 years. During the period April-Dec'01 the capacity utilisation is 72.5% but this is due to HOC internal problem and not due to increase in imports.
- v. It is seen that during the same period the other manufacturer of Phenol, Herdillia Chemicals. Limited (HCL) has produced 23928 MT (31904 MT annualized) against 29804 MT produced by it last year (7% increase). Thus it was not the market conditions, which was responsible for lower production of HOC but on the other hand the low production of HOCL resulted in imports of phenol in to the country.

D. Examination and Findings by the Authority

- 14. The submission made by the petitioners, importers, exporters and other interested parties, to the extent filed before the Authority have been examined and considered while arriving at these findings and wherever appropriate have been dealt hereinafter.
- ii) The Authority confirms, in the absence of complete and sufficient response from the exporters from subject countries in the form and manner prescribed, having made the findings with regard to exports from subject countries on the basis of the facts available to it as per rule 6(8) supra.

- iii) The cases of new exporters or those stated to be willing to give price undertaking should be considered, on request, by the Authority in accordance with the Rules supra.

Product under Consideration and like article

- 15. The Product under consideration in this investigation is Phenol also known as carbolic acid. Benzene and LPG are two major inputs required in the production of Phenol. Cumene is manufactured by the reaction between propylene and benzene in the presence of solid phosphoric acid catalyst at high pressures and elevated temperatures. Phenol is produced by oxidation of cumene using air at elevated temperatures and pressures. The product is cumene hydroperoxide at lower concentration, which is then alkali washed and concentrated to a higher strength. This is then mixed with H₂SO₄, which causes a reaction to give phenol and acetone. Phenol is a basic organic chemical classified under Chapter XXIX of Customs Tariff Act under sub heading 2907.11 and subheading 2707.60 under Chapter XXVII of Customs Tariff Act. The present investigations are in respect of the product under consideration irrespective of the classification under which they are imported. Custom classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigations.
- ii. Rule 2(d) of the Anti-dumping Rule specifies that like articles mean an article, which is identical and alike in all respects to the product under investigation or in the absence of such an article, another article having characteristics closely resembling those of the articles under examination.
- iii. The petitioner claimed that the goods produced by him are like articles to the goods originating in or exported from subject countries. However, some of the exporters and importers have argued that the phenol imported by them are different in quality. However, no evidence has been adduced by them to indicate that imported phenol is not substituting the domestically produced phenol either technically or commercially. The Authority notes that phenol produced by domestic industry has characteristics, which are similar to those of the phenol imported from subject countries. In view of the above the Authority holds that phenol produced by the domestic industry and those being imported from the subject countries are like articles within the meaning of the rules for the purpose of injury determination.

De Minimis Limits

- 16. As regards ascertaining that the imports from the subject countries during the period of investigation (POI) are above de-minimis levels, the Authority has examined the contention of the

petitioner not to accept the DGCI&S published data for the subject goods as import statistics brought out by DGCI&S is incomplete and quite a large number of transactions are not reported in their data. The Authority has crosschecked the data submitted by the petitioner with the data furnished by Kandla port customs and notes that DGCI&S data for the POI is incomplete and large imports especially bulk imports from south Africa and imports from European union is not reflected correctly. The authority has therefore taken kandla customs port data for determining imports from South Africa (bulk imports) and European union and has gone by the submissions of exporters from South Africa (drum imports) and Singapore. Thus authority notes that the imports of subject goods from subject countries during POI are above de-minimis.

Country Name	Quantity (MT) POI	%Age share in imports (POI)
Singapore	****	27.48
South Africa	****	15.84
European Union	****	31.2

Domestic Industry

17. The petition has been filed by HOCL, Mumbai on behalf of the domestic industry. The petitioners have claimed that they account for almost 47% of the total Indian production of the subject goods. A large number of exporters/importers/users have argued that the petitioners do not have the standing to file the applications. They have quoted 5(3) of the anti dumping rules which says that the DA shall not initiate any investigations pursuant to the application made under sub rule (a) unless it determines on the basis of an examination of the degree of support for, or opposition to the application expressed by domestic producers of the like product that the application has been made by or on behalf of the domestic industry provided that no investigation shall be initiated if domestic producers expressly supporting the application account for less than 25% of the total production of the like article by the domestic industry. It has also been explained in the sub rules that the application is deemed to have been made by or on behalf of the domestic industry if it is supported

by those domestic producers whose collective output constitutes more than 50% of the total production of the like article produced by that portion of the domestic industry expressing, either support for or opposition as the case may be to the application.

18. The Authority has examined the contention made by importers/users/exporters in this regard as well as the evidence available on record. It is seen that M/s Herdillia Chemicals Ltd (HCL) is another major producer of Phenol in this country and has supported the petition filed by HOCL. However the Authority notes that the Herdillia Chemicals Ltd has imported the subject goods during the POI from subject countries and thus they cannot be treated as part of domestic industry and therefore Authority has excluded them in further investigations. Excluding Herdillia Chemicals Ltd, the domestic industry satisfies the criteria of standing.

Thus, the Authority holds that petitioners satisfy the criteria of standing to file the petition on behalf of the Domestic Industry in terms of Rule 5(3) (a) of the Rules supra, for the purpose of preliminary finding. The Authority also considers these petitioner companies as 'domestic industry' within the meaning of Rule 2(b) supra.

E. DUMPING & EXAMINATION OF CLAIMS MADE ON NORMAL VALUE & EXPORT PRICES

Normal Value

19. Under Section 9A(1)© of the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 normal value in relation to an article means:

“(i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(ii) When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either –

(a) Comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) The cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general

costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6)";

20. The Authority sent questionnaire to all the known exporters for the purpose of determination of normal value in accordance with Section 9A(1)©. The Authority received responses from the following exporters and exporters association.

1. Mitsui & Co Ltd. Singapore Branch.
2. Mitsui Phenol Singapore Ltd(MPSL), Singapore.
3. Merisol RSA (pty) Ltd, South Africa.

21. The Authority notes that M/s Mitsui & Company Ltd is a public company Incorporated and listed in Japan. They have exported to different companies in India during POI though they donot have any domestic sales. On the other hand M/s Mitsui Phenol Singapore Pte Ltd, Singapore has exported to India during the POI through trading houses and they have made domestic sales also during this period.

Normal value and Export Price determination for Singapore:

22. Only M/s. Mitsui & Co Ltd, Singapore branch and M/s Mitsui Phenol Singapore Ltd have responded from amongst the exporters of Singapore. M/s Mitsui Phenol Singapore Pte. Ltd. has given information relating to sales made in the home market and they have given an account of volumes sold along with invoice numbers and dates as per appendix I. They have added that they had sold phenol into India via Trading Houses and they have given customers names and addresses along with the details of shipment made. However they have not enclosed any profit and loss statement and balance sheets for the last three years in their submissions. The Authority also notes that the exporter has not submitted any information regarding financing and interests costs as required in the Appendix-8,9 and 10 in their submission as per their response to the questionnaire.

However the Authority notes that they have submitted the different transactions pertaining to domestic sales by giving invoice numbers, date volume sold and rate per unit in Appendix 1, which indicates that their sales have been made under ordinary course of trade. The Exporter has also submitted information with regards to Appendix 3, which shows the export to India and domestic market sales. They have also submitted Appendix 4 and Appendix 5, which show sales price structure for exports to India and Sales price structure to Domestic sales. Further they have submitted the information under

major heads excepting financial and interests costs as per Appendix 8 & 9 which gives the ex factory price for domestic sales and sales price for export to India. The Authority, for the purpose of preliminary determination, accepts the data submitted by the exporter for normal value and export price determination by taking ex factory price for domestic sales as normal value on weighted average basis and ex factory price for sales to India as Export price also on weighted average basis subject to further verification and investigation.

The Authority notes that the exporter has made sales of **** MT in the home market for US\$**** and as per Appendix 5 the ex factory price after making adjustments towards commissions, freight etc comes to US\$****. The Authority also notes that the firm has exported ****MT at the rate of US\$ **** during the POI and ex factory price after making all adjustments come to US\$****. As per Anti-Dumping agreement comparison of normal value and export prices should be made at the same level, preferably at the ex factory level. However since the normal value and export price has been taken at ex factory level, no further adjustments are required to be made in these values. The authority has determined normal value as US\$**** and Export price as US\$****. Accordingly the dumping Margin comes to US\$ **** or 28.75% of the export price.

M/s. Mitsui & Co. Ltd. Singapore Branch has submitted similar arguments as made by M/s Mitsui Phenol Pte Ltd. Singapore. They have not submitted any information as per appendix I of the questionnaire. However, as per appendix III, they have confirmed that they do not any domestic market sales. They have given an account of exports made to India by giving customers names and addresses along with details of shipments made. They have given further information as regards sales price structure for exports to India and countries other than India. They have also calculated the price at the ex factory level for exports to India after making adjustments towards discounts/commissions and overseas freights. However they have not submitted any information towards appendix VII onwards and therefore, the Authority is constrained to admit the submissions made by the exporter in totality. However, the Authority has accepted the exporter's submissions for the limited purpose of preliminary findings subject to further verification and investigation. The Authority notes that the firm has exported **** MT of subject goods to India for a total value of US \$ **** during the period of investigation and their ex factory export price has been taken as US \$ **** after making adjustments towards discounts/commissions and overseas freight. The firm has claimed that they made exports to third country and they had given an account of third country sales during POI. However, the authority has taken the domestic selling price for Mitsui & Co by referring to the data provided for M/s Mitsui

Phenol Singapore Pte Ltd as mentioned in the previous paragraph being the best information available in terms of 6(8) of Anti dumping rules and since both the exporters are in same country with prices determined by the market forces. The Authority has therefore taken the normal value for Mitsui & Co. Ltd. as US \$ ****. Since the exporter has not submitted information pertaining to appendix 7 onwards, no exporter specific adjustments can be granted to M/s Mitsui & Co in the normal value computation. The dumping margin for M/s. Mitsui & Co. comes to US\$ **** or 28.50% of export price.

Other Exporters from Singapore

- 23 As regards determination of normal value for other non-cooperating exporters, the authority has taken normal value as determined in the case of M/s Mitsui & Co. Singapore as mentioned in the preceding paragraph. As regards the export price the Authority has taken the lowest export price from Singapore to India during POI as the export price for non-cooperating exporters. The ex factory export price has been arrived after making adjustments towards commission, ocean freight and insurance. The authority has determined normal value as US\$**** and Export price as US\$**** for non-cooperating exporters. The Dumping margin for Non-cooperating exporters comes to US\$. **** Or 53.42% of the export price.

Normal Value and export price for Merisol RSA(pty), South Africa

24. M/s. Merisol RSA (pty), South Africa has responded to the questionnaire but has given incomplete information with regards to the different Annexure. As per the Appendix 1 they have submitted detailed information about the various sales in their domestic market by mentioning the invoice numbers, volume sold, sales value and rate per unit. They have also given invoice numbers of their domestic sales with quantity and rate per unit with respect to two principal grades, drum sales and bulk sales. In the Appendix 2 they have submitted an account of Phenol exports to India for the POI. They have backed this information by giving an account of sales to Indian customers by name giving a breakup of invoice values, ocean freight, insurance, commission, etc. In the Appendix 3 they have given an account of exports to India, sales to third countries and also sales in their domestic markets. They have submitted Appendix 4 and 5 giving sales price structure for exports to India and sales price structure for their domestic sales. However they have not given sufficient information regarding their other product's quantity and value. However they have given an account of factory costs and profit of exports to India and for their domestic market with regards to their bulk and drum sales though they have not submitted required

information about their financing and interests costs and they have not submitted net profit which they have added to their ex factory costs in the Appendix 8 and 9.

The Authority has gone through the submissions of the exporter and is inclined to accept the submissions of the exporter for the limited purpose of Preliminary findings subject to further verification and investigations. The Authority notes that M/s Merisol SA has sold ****MT in bulk sales for US\$**** and ****MT in drum sales for US\$**** in their domestic market during POI. The Authority has determined normal value as US\$**** and US\$**** after making adjustments towards inland freight, insurance, storage and handling costs as submitted by exporter as ex factory price of sales (bulk and drum respectively) in the domestic market. Since these normal value and export price have been taken at ex factory level, no further adjustments are required to be made in these values. As regards determination of export price, the Authority notes that the exporter has exported ****MT of subject goods to India for a value of US\$**** at the rate of US\$**** for bulk sales and ****MT for US\$**** at the rate of US\$**** for drum sales. Thus export price has been determined at the ex factory level after making adjustments towards inland freight, handling, insurance, overseas freight, overseas commission etc as worked out by exporter and thus export price has been worked out as US\$**** for bulk sales and US\$**** for drum sales.

As per the Anti-Dumping agreement comparison of normal value and export prices should be made at the same level, preferably at the ex factory level. However since the normal value and export price has been taken at ex factory level, no further adjustments are required to be made in these values and Dumping margin comes to US\$ **** or 42.24% of the export price for bulk sales and US\$ **** or 36.48% of Export price.

Normal Value and Export Price for other exporters from South Africa

25. As regards determination of normal value for other non-cooperating exporters, the authority has taken normal value as the weighted average domestic sales price at ex factory level both for bulk sales and drum sales.

As regards the export price, the Authority has taken the lowest export price from South Africa to India during POI as the export price for non-cooperating exporters both for bulk as well as drum sales. However since these normal value and export price have been taken at ex factory level, no further adjustments are required to be made in these values. The authority has determined normal value as US\$**** and US\$**** for bulk sales and drum sales respectively and Export

price as US\$**** and US\$**** both for bulk sales and drum sales respectively for Non-cooperating exporters. Dumping margin comes to US\$ **** or 101.32% of Export price and US\$**** or 62.40% of export price for bulk and drum sales respectively.

Normal value and Export Price for European Union

26. The Authority notes that none of the exporters from EU has filed any response. As no information about domestic sales price structure of the subject goods, its cost of production in EU and other information as per the questionnaire has been furnished, the Authority has proceeded to rely upon the best available information for determination of normal value. The petitioners have claimed normal value in respect of EU on the basis of constructed cost of production. The Authority finds that none of the exporters have given any information to enable it to determine the normal value based on the domestic sales price. The Authority confirms, in the absence of any response from the exporters from subject countries in the form and manner prescribed, having made the findings with regard to exports from subject countries on the basis of the facts available to it as per rule 6(8) supra.

Accordingly, the Authority has constructed the normal value on the basis of cost of production details as made available by the petitioner with the applicable adjustments. The normal value so determined for EU is US \$ ****

The Petitioner has submitted information regarding imports of subject goods from European Union. The Authority notes that the European Union has exported ****MT for US\$**** at the rate of US\$****. The Authority has arrived at export price from European Union to India on the basis of the DGCIS data for POI and after making adjustments for ocean freight, overseas insurance, commission, port expenses, inland freight, the export price comes to US\$**** at the ex factory level. The Dumping margin comes to US\$**** or 97.72% of the export price.

	Country	Dumping Margin %
1.	European Union	97.72
2.	Singapore	
	Mitsui & Co.	28.50
	Mitsui Phenol Singapore Ltd.	28.76

	Other Exporters	53.42
3.	South Africa	
	a. Merisol, RSA	
	1. Bulk sales	42.24
	2. Drum sales	36.48
	b. Others	
	1. Bulk sales	101.32
	2. Drum sale	62.40

F. INJURY

27. Rule 11 of Anti Dumping Rules reads as follows:

“Determination of Injury:

(i) In the case of imports from specified countries, the designated authority shall record a further finding that import of such article into India causes or threatens material injury to any established industry or materially retards the establishment of any industry in India;

(ii) The designated authority shall determine the injury to domestic industry, threat of injury to domestic industry, material retardation to establishment of domestic industry and a causal link between dumped imports and injury, taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on price in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles and in accordance with the principles set out in Annexure II to these rules.”

(iii). The principles for determination of injury set out in Annexure-II of the Anti- Dumping Rules lay down that:

a. A determination of injury shall involve an objective examination of both (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for like article and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products.

b. While examining the volume of dumped imports, the said Authority shall consider whether there has been a significant increase in the

dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. With regard to the effect of the dumped imports on prices as referred to in sub-rule (2) of Rule 18 the Designated Authority shall consider whether there has been a significant price under-cutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred to a significant degree.

28. Views of the petitioners

The domestic industry is suffering from dumping of Phenol from South Africa, Singapore and European Union. Annexure 2(2) of the Anti-Dumping rules provide that in case imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to Anti-Dumping investigations, The Designated Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that

- a. The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than 2% expressed as percentage of export price and the volume of imports from each country is 3% of the imports of the like articles or where the export of the individual countries less than 3%, the imports cumulatively accounts for more than 7% of the imports of like article, and
- b. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of conditions of competition between the imported articles and the like domestic articles.
- c. The margins of dumping from each of subject country are more than the limits described above (de-minimus).
- d. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate since the exports from the subject countries directly compete with the prices offered by the domestic industry in the Indian market. The Authority is therefore requested to assess injury to the domestic industry cumulatively from subject country.
- e. There has been substantial increase in imports from the subject countries in absolute terms and the markets share of imports from subject countries has also increased.
- f. The volume of imports has increased in spite of imposition of safeguard duty. Evidently, safeguard duty has not been deterrent to the importers. Export price from the subject country has declined significantly and decline in export price in US dollars are much more significant than Indian rupees. In fact the prices have declined lower than the landed value of imports of subject goods and is significantly below the selling price of the domestic industry.

- g. The production and capacity utilization of the domestic industry has very significantly declined in the current year as per the table below. Hence, the domestic industry has been forced to restrict its production due to dumping from subject countries.
- h. The selling price of the domestic industry has increased during the POI but the increase in prices was lower than the increase in the cost due to increase in raw material and fuel cost. However, the prices of imported phenol when adjusted for costs increases, actually fell even below the already low level of the year 1998-99. Thus, the cost increase adjusted sales realization of the domestic industry declined.
- i. The prices at which the material is being exported into India is not below the selling prices of the domestic industry but is not permitting recovery of full cost of production to the petitioner and hence the imports are causing severe price under cutting, depression, suppression in the market.
- j. The domestic industry is losing substantial sales from its regular customers in favour of traders importing phenol.
- k. Though there is no significant change in the employment level in the petitioner's companies. However, this is because of labour related legislation in the country due to which retrenchment is virtually impossible.
- l. The sales of phenol at prices significantly below the cost of production and fair selling price has resulted in heavy losses in the domestic industry and domestic industry has been forced to sell at a price which do not permit recovery of full cost of production leave alone profit.
- m. The injury to the domestic industry is directly being caused due to dumped imports from the subject countries.

Views of Exporters, Importers and Users/Associations

29. There are only two manufacturers of phenol in the countries namely HOCL & HCL who account for 98% of the total capacity established in the country. It is seen that HOC and HCL were jointly increasing prices of Phenol. Moreover it is also evident that both HOCL & HCL are charging the same price for the last many years and the prices are also changed upwards or downward exactly on the same date. It is to be further seen that with the same price the HCL made profit for the period of 3 quarters for the current year for the period ending up to 31st Dec'01, whereas HOC claims that it has made loss in this period on phenol. It will be appreciated that there can not be such a major

loss in case of one company and profit in case of other when both of them are selling their products at the same market rate.

- a. HOC had stated that it has implemented cost reduction scheme as part of adjustment plans committed to DG (Safeguard). It is seen from the findings of DG (Safeguard) that the phenol manufacturers had promised to achieve cost reduction of Rs.6000/MT in its first application for SGD and when it was sought to be extended by another 2 years, HOC had committed further cost saving of Rs. 3726/MT. Thus there was a plan to achieve cost saving of Rs. 9726/MT. The total increase in income due to such cost saving on the production of 40,000 TPA of phenol alone works out to Rs. 36.34 crore per annum. In addition HOC had also committed to achieve cost reduction in case of Acetone (a co-product of Phenol) of the order of Rs. 7467/MT (Annexure-17) which means saving of Rs.17.92 crore for its rated capacity of 24000 MT. Thus the prices of phenol should have been reduced considerably. It is however seen that the net sale realization of phenol actually increased by 44% in the year 2000-01 as shown above. Thus the benefit of cost reduction was not passed on to the customers of phenol, which resulted in increase in imports of phenol in the country.
- b. Though the SGD has been reduced from 15% to 10% from July'01 it is to be noted that the SGD was originally sanctioned only for 2 years on the commitment given by the phenol manufacturers to achieve cost reduction and discontinue the Safeguard duty. Further at that reduced rate of SGD the protection of duty being received by Phenol manufacturers is 35% (basic 25% + SGD10%), which is very high in the present duty regime. It is also to be noted that the USD rate in Indian rupees also went up from Rs. 42.95 in June'99 to Rs. 48.72 at present, which has resulted in 13.43% additional protection in import duty which was not intended.
- c. It is seen that HOC had made very high profit in the year 2000-01 which were 192% of the profits in 1998-99 and 215% of the profits in the previous year. Evidently HOC used the SGD protection and its joint marketing strategy with HCL to increase the prices to very high levels which affected the operational cost to phenol user industry to such an extent that phenol users like Bakelite Hylam have even closed down their operations. In fact imposition of SGD for 2 years and its further extension for another 2 years was very strongly opposed by the phenol users in India and it was brought to the notice of DG (Safeguard) that such a protection will be used at the cost of phenol based industry for covering up the losses made by phenol manufacturers in their other product lines.

G. Examination by the Authority.

30. Analysis of injury to the domestic industry has been done on the basis of the Information available on record and the verification done by the officials of the Director general of Anti Dumping & Allied Duties. The following parameters have been analysed for the purpose of assessment of injury to the domestic industry.

Sales Volume and Value

The Authority observes that there is a decline in the sales volume as well as the sales value in the POI as compared to the previous year. The unit price realisation has also gone down by about 26% in the POI over the previous year.

Volume and Market Share of Dumped Imports

31. The Authority has examined the information regarding the volume of exports from the subject countries during the period of investigation and the preceding years. During the POI the imports from the three subject countries taken together were 36726Mt as compared to the total imports of 46418 MT from all countries. During the year 2000-2001 the imports from subject countries were 4501MT out of total imports of 14298MT in the country. In percentage terms the imports from subject countries accounted for a market share of 64.3% in 1999-2000, 31.48% during 2000-01 and 79.43% during POI. When compared to the previous year 2000-01 the share in the market has shown a significant increase during the POI. Even in volume terms, the imports from the subject countries during POI showed an increase of 332% over the imports in the previous year. The increase in market share is very significant and the increase in imports in absolute terms does hold a threat for the domestic industry. The Authority notes that there has been a significant increase in the dumped imports in absolute terms.

Country	European Union		Singapore		South Africa	
Year	Qty MT	% Share	Qty MT	% Share	Qty MT	% Share
2000-01	****	11.05	****	0.58	****	3.34
POI (9 Months)	****	26.58	****	40	****	13
POI Annualised	****	26.58	****	40	****	13

Market Share of Imports from Subject countries			
Year	Imports From Subject Countries MT	Total Imports MT	% Share
1999-2000	18730	29128	64.3
2000-2001	3502	14298	31.48
POI Annualised	****	****	79.43

32. Market Share of Imports from Subject Countries (% of the Total Demand)

The Authority has calculated the total demand in the country by adding the total imports to the sales of the domestic industry as well as other producers of the product under consideration. The Authority notes that the imports from the subject countries could acquire a market share of 40% of the total demand in a short span of 9 months.

Year	Imports from Subject Countries MT	Total Demand MT	% Share
1999-2000	18730	98764	22.92
2000-2001	4502	81691	5.51
POI (Annualised)	****	****	40.59

Production and Lower Capacity Utilisation

33. It has been stated by the exporters that the demand for the subject goods has grown in the country at a faster pace and the rise in the imports have been due to the short fall in the domestic production of the subject goods. However the domestic industry has claimed that despite the existence of the growing market, their losses have gone up due to indiscriminate dumping by the subject countries. The Authority observes that capacity utilization of the domestic industry has worsened in the POI and as a consequence its production has declined in the POI as compared to previous year.

The petitioner company accounts for 47% share, i.e. a major proportion of the domestic production of the subject goods during the POI and have been construed as 'Domestic Industry' in terms of Rule 2(b) supra and so stated in foregoing Para 13 of these findings.

Therefore, the Authority holds the view that the domestic industry has suffered injury on account of decline in production and capacity utilization. The sales volumes of the domestic industry as represented by the petitioner companies also declined during the POI by 26% in comparison to the previous year. Various exporters and importers have argued that the long shut down period which were much above the industry average was responsible for the decline in production and hence the decline in capacity Utilisation. The Authority has examined these facts in detail after on spot verification at the plant site and have come to the conclusion that it was because of large inventory piled up inside the Phenol storage tanks (which incidentally cannot be stored in other containers and which have to be consumed/off taken before fresh production can be started) that were responsible for the frequent shutdown apart from the normal maintenance shutdown. In fact the authority is inclined to hold the view that it was dumping which led to the low off take of phenol resulting in large pile up and hence frequent shutdown. Volume).

	Unit	1998-99	1999-00	2000-01	POI	POI Annualised
Effective Capacity	MT	45000	45000	49000	49000	49000
Production	MT	40142	39261	39055	29008	29008
Capacity Utilization	%	89.2	87.25	79.7	59.2	59.2
Opening Stocks	MT	2464	2885	1517	1920	2560
Closing stocks	MT	2885	1517	1920	2399	3199
Indigenous sales	MT	39956	40325	38633	28384	28384
Cost of Production *	Rs./MT	100	103.69	133.47	135.82	135.82
Selling Price*	Rs./MT	100	94	140	108.31	108.3
Profit/Loss *	Rs./MT	100	48	173	-25	-25
Net Block	Rs.Lacs	*****	*****	*****	****	
Gross Block	Rs. Lacs	****	****	****	****	

Price Undercutting and Price Underselling

34. As regards the impact of the dumped imports on the domestic industry the principle (iv) of Annexure-II of the Anti-Dumping Rules states:

"The examination of the impact of the dumped imports on the domestic Industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilisation of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments."

In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree. The Authority has compared the landed value of imports of subject goods from subject countries during the POI with the net sales realization and has found that there has been a significant price under-cutting by the dumped imports. The landed value of imports has been found to be significantly lower than the domestic industry's net sales realization.

The Authority has also examined the claim of the petitioner that the domestic industry is suffering on account of the losses. The Authority notes that price underselling is an important indicator to make an assessment of the injury. The Authority has worked out the Non-injurious price for the product under consideration and compared the same with the landed value to arrive at the extent of price underselling. The analysis shows a significant level of incidence of price underselling causing injury to the domestic industry. The imports were having significant suppressing/ depressing effect on the prices in the domestic market, as the domestic industry had not been able to raise its selling price in view of the dumped imports. Thus examination of the available evidence shows that the domestic industry as a whole has suffered injury on its sales of subject goods during POI.

Selling Price / Profitability

35. The authority notes that selling* prices of the domestic industry is significantly below the price, which would have permitted the domestic industry, a fair recovery of its cost of production and earn a

reasonable return. Thus, the dumped imports have prevented the domestic industry from effecting legitimate price increase to realise a reasonable price. The industry has suffered material injury on account of depressed selling prices resulting in non-recovery of cost of production and thereby suffering financial losses.

Other injury parameters evaluated by the authority are as follows:

- a. The employment levels of domestic industry have not undergone any significant change during the period of investigation.
- b. There is a marked rise in the closing stocks during POI indicating that there is a significant change in the inventory position of the domestic industry during the period of investigation.
- c. Some exporters/Users have opined that during the POI, HCL has made profits and HOCL has incurred loss. They wanted the authority to examine this issue. The Authority has examined the records submitted by HCL and has come to a conclusion that there is no truth in the submission that HCL made profits during the POI. In fact they had made a loss of Rs **** during POI.
- d. The most significant parameter evidencing injury is the price undercutting and price underselling. On the basis of the evidence available before the Authority, it is determined that the domestic industry has suffered injury.
- e. Thus the Authority notes that injury to the industry has been caused by the dumped imports of subject goods from the subject countries. As the landed value of the subject goods is significantly below the selling price of the domestic industry, the industry has been forced to keep its selling price significantly below the cost of production.

Month/Year	Cost of Production Rs MT	Net sales Realisation Rs MT	Profit/Loss Rs. MT
98-99	100	100	100
99-00	103	94	48
2000-01	133	140	173
Apr.01- June-01	135	132	115

July 01- Sept 01	132	107	-13.5
Oct.01 – Dec 01	140	87	-170
POI	135	108	-25

Indexed figures considering 1998-99 as 100.

- f. It is evident from the table above that the domestic industry which was making profits during years 98-99, 99-00 & 00-01 started incurring losses during the POI due to decrease in selling price. The Authority notes that the same has been caused by direct results of imports at dumped price.

Cumulative assessment of injury

36. As per annexure-II (iii), in cases where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to Anti-dumping investigation, the Authority is required to cumulatively assess effect of such imports, only when it determines that (a) the margin of dumping established in relation to imports from each country is more than 2% expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is 3% of the imports of like article --- and (b) cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic article. The Authority has found that the margin of dumping in respect of each of the subject country is more than 2% and the volume of imports from each country is also more than 3%. The Authority has also found it appropriate to cumulatively assess the effect of imports of the subject goods on the domestically produced like article and has found that there is a cumulative effect of injury by imports of subject goods on the domestic industry.

The above economic parameters cumulatively and collectively establish that domestic industry has suffered material injury on account of dumping.

H. CAUSAL LINK

37. Annexure-2 (v) of Anti-Dumping rules states that it must be demonstrated that dumped imports are, through the effects of dumping as set forth in Para 2 and 4 of said annexure above, causing injury to the domestic industry. The demonstration of a causal relationship between the dumped imports and the injury to the domestic industry shall be based on an examination of relevant

evidence before the designated authority. The designated authority shall also examine any known factors other than the dumped imports, which at the same time are injuring the domestic industry, and the injury caused by these factors must not be attributed to dumped imports. Factors which maybe relevant in this respect include inter-alia, the volume and price of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry.

Views of the Petitioners:

38. The petitioners have stated that injury to the industry has been caused by the dumped imports of subject goods from the subject countries. As the landed value of the subject goods is significantly below the selling price of the domestic industry, the industry has been forced to keep its selling price significantly below the cost of production. Therefore, the industry has not been able to realise a non-injurious price. The price suppression suffered due to dumped imports has resulted in severe financial losses to the domestic industry. The industry has also been prevented from increasing its sales and production. The domestic industry has also stated that there has not been a contraction of demand of the subject goods and the injury to the industry cannot be attributed to any fall in demand.

Examination by the Authority

39. In determining whether material injury to the domestic industry was caused by the dumped imports, the Authority took into account the following facts: -

a. The authority observes that there is a single market for the subject goods where dumped imports compete directly with the goods produced by the domestic industry. Decline in demand is not a factor causing injury to the domestic injury. The imported subject article and the domestically produced goods are like articles and are used for the same applications/end uses. Thus, pricing becomes the most important factor determining purchase of the article from either imported sources or domestic sources.

b. The imports from Subject countries suppressed the prices of the product in the Indian market to such an extent that the domestic industry was prevented from recovering its full cost of production and earn a reasonable profit from the sale of subject goods in India.

c. Substantial imports of subject goods from Subject countries at dumped prices during POI has resulted in substantial losses to the domestic industry.

I. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST

40. The purpose of anti dumping duties is to eliminate dumping which is causing injury to the domestic industry and to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country.

ii. The Authority recognises that the imposition of anti dumping duties might affect the price levels of the products manufactured using subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products. However, fair competition on the Indian market will not be reduced by the anti dumping measures. On the contrary, imposition of anti dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods. The Authority notes that the imposition of anti dumping measures would not restrict imports from Subject countries in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The consumers could still maintain two or even more sources of supply.

J. OTHER ISSUES

Issue of Safeguard:

41. It has been argued by some interested parties that since the safeguard duty has been imposed on the subject product originating from the subject countries, there is no need for any Anti-Dumping duty as safeguard duty has addressed the issue of serious injury which is a part of material injury that Anti-Dumping duty addresses. There are also arguments that after having got the redressal by way of safeguard duty, the domestic industry can not have double benefit by the way of anti dumping duty also.

The Authority has examined the issues concerning this case where safeguard duty has been imposed prior to the initiation of anti dumping investigations and concludes that

1. The POI in the safeguard investigation was different than the present investigation and hence the injury determination cannot be assumed to be the same and correlated.

With regard to the argument that the DG, Safeguards has removed serious injury and the same implied removal of material injury also, the Authority notes that the nature of injury has materially changed with exporters now resorting to unfair pricing from a situation of fair pricing (safeguard duty). The Authority concludes that petitioner now

needs the protection of anti dumping when the exporters have resorted to unfair pricing of their products. Hence, there is no merit in the argument raised by exporters/users regarding double protection being accorded to the petitioner. It has been claimed by the exporters and importers/users that imposition of anti dumping duty would amount to double protection to the domestic industry. On the other hand the domestic industry has submitted that the safeguard duty has been imposed on the imports of the subject goods to take into account injuries (serious injury) coming out of fair imports as against unfair imports for which anti dumping duty is required. The authority has carefully considered the issues in this regard and notes that the purpose of Anti dumping investigations is to examine whether the firm is undergoing any injury due to unfair imports from subject countries during POI. The Authority feels that occurrence of injury is common in anti dumping and safeguard investigations and the imposition of anti dumping and safeguard duty is to grant protection to the domestic industry for a limited timeframe against dumped/unfair and fair imports respectively. The authority concludes that while calculating injury margin, the safeguard duty would be taken into account in determining landed value of subject goods from the subject countries.

Issue relating to Monopoly

42. It has also been argued by some interested parties that HOCL is the only producer of the subject goods in the country besides Herdillia which has been taken over by Schenectady and therefore, the present petition has been filed by them to avoid any competition. Further, the total capacity of the petitioner is short of the demand of Phenol in the country and the size of the plant is too small to cater to total demand of the in this country. It has also been argued that the technology used by the domestic industry is obsolete. Issues have also been raised regarding the poor quality of the goods produced by the domestic industry as well as the methodology adopted for apportionment of fixed costs, depreciation and overheads to the production of Phenol. It has also been stated that the prices of exports to India are at the prices prevailing in international market.

iii). The Authority has examined the above issues. The purpose of anti dumping duty is to ensure that any injury caused to the domestic industry due to dumping is addressed adequately. The fact that there is a single producer of the subject goods in the country (apart from Herdillia which has been taken over by Schenectady) does not, in any way, restrict the right of the domestic producers to claim relief from the Designated Authority against the dumped imports under the Anti Dumping Rules. It has been the accepted position that anti dumping duty is in the nature and form of providing a remedy against the trade distorting practice of dumping. Further, anti dumping duties do not propose to restrict or block imports from any sources and therefore,

the issue of the domestic supply being short of the total consumption in the country, has no relevance. Also since alternative sources of supply are available to the Indian industrial users, the apprehension of the petitioner company exercising monopoly position to exploit the customers is misplaced.

Issues relating to data from DGCI&S and secondary sources

43. It has been claimed by the exporters and associations of user industries in India that import data submitted by the domestic industry should not be accepted for injury determinations as these data have been taken from secondary sources and the authority should only take data from the primary sources (DGCI&S) into account in their anti dumping investigations. The Authority has examined this issue and has noted that DGCI&S data for imports of the subject goods are very much at variance with data submitted by the exporters and domestic industry. The Authority also notes that much of the subject goods cargo had arrived at Kandla port. The Authority has crosschecked the data submitted by the petitioner and exporters with import data furnished by Kandla port Customs and after crosschecking the data, the authority concludes that DGCI&S data is largely incomplete and does not indicate all the transactions from the subject countries during the POI. The authority has therefore taken the port data furnished by Kandla Customs for imports of subject goods from European Union and all bulk imports from South Africa. For drum imports from South Africa the authority has taken into account exporters submission. As regards imports from Singapore, the authority has taken data from the Singapore Trade statistics for the imports of subject goods into India from Singapore and has gone by exporters submission with regards to imports from Singapore.

J. CONCLUSIONS

44. The Authority has, after considering the foregoing, concludes that :

- (i) Phenol or product under consideration has been exported to India from subject countries below its normal value;
- (ii) The Indian industry has suffered material injury;
- (iii) The injury has been caused by the dumped imports from subject countries;
- (iv) The Authority considers it necessary to impose an anti dumping duty provisionally, pending final determination, on all imports of Phenol from subject countries in order to remove the injury to the domestic industry. The margin of dumping determined by the

Authority is indicated in the paragraphs above. The Authority proposes to recommend the amount of anti dumping duty equal to the margin of dumping or less, which if levied, would remove the injury to the domestic industry. For the purpose of determining injury, the landed value of imports is proposed to be compared with the non-injurious selling price of the petitioner companies determined for the period of investigation.

(v) Accordingly, the Authority recommends that the provisional anti dumping duties be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government on all imports of Product under consideration originating in or exported from subject countries pending final determination. The anti-dumping duty shall be the amount indicated in the table below, to be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government on all imports of Phenol falling under chapter 29 and 27 of Customs tariff, originating in or exported from Singapore, South Africa and European Union.

Serial Number	Countries/exporters	Amount of Duty (US\$ Per MT)
1.	Singapore: a. Mitsui & Co. Ltd b. Mitsui Phenol Singapore Pte Ltd c. Other Exporters	95.77 101.62 161.38
2	South Africa a. Merisol RSA 1. Bulk Sales 2. Drum Sales d. Other exporters 1. Bulk Sales	89.12 24.76 222.74

	Sales 2. Drum Sales	130.60
3.	European Union	109.49

vi). Landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 and all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

K. FURTHER PROCEDURE

45. The following procedure would be followed subsequent to notifying the preliminary findings:

- a. The Authority invites comments on these findings from all interested parties and the same would be considered in the final findings;
- b. Exporters, importers, petitioner and other interested parties known to be concerned are being addressed separately by the Authority, who may make known their views, within forty days from the date of preliminary findings. Any other interested party may also make known its views within forty days from the date of publication of these findings;
- c. The Authority would provide opportunity to all the interested parties for making oral submissions, which have to be rendered thereafter in writing;
- d. The Authority would conduct further verification to the extent deemed necessary;
- e. The Authority would disclose essential facts before announcing final findings.

L.V. SAPTHARISHI, Designated Authority